RNI-UPHIN/2009/30721

दिल्ली
अधिकतम तापमान 33 डिग्री
न्युनतम तापमान 27 डिग्री
एनसीआर
अधिकतम तापमान 32 डिग्री
न्युनतम तापमान 26 डिग्री

बुधवार 02 जुलाई 2025
सुर्योदय प्रातः 05:28 बजे
सूर्यास्त सांय 19:24 बजे

एनसीआर टुडे

करंट न्यूज करंट व्यूज

पृष्ठ 4 किसान-खाद्य सुरक्षा के विरुद्ध हैं ये सिफारिशें

उत्तर प्रदेश और दिल्ली से एक साथ प्रकाशित | वर्ष: 16 | अंक : 257 | गाजियाबाद, बुधवार 02 जुलाई 2025 | मूल्य : ₹ 2 | पेज : 06 | विक्रमी संवत् 2081 | युगाब्द 5126 | शाक 1946

केनरा बैंक Canara Bank
SCAN & PAY
UPI ID: 300012627000246@cnrb
BHIM UPI
Canara ai1 | CBDC | Paytm
Cred | PhonePe | Google Pay
DIGITAL RUPEE ACCEPTED HERE

NCR MASALA
India's Premium Masala
9410855900
ncrmasala@gmail.com
get online www.ncrmasala.com
गर्म मसाला, हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा व अन्य रसोई मसाले

शिक्षा ही सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम: मुर्मू

✷ एनसीआर टुडे. गोरखपुर ✷

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि शिक्षा ही महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। श्रीमती मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के अकादमिक भवन, प्रेक्षागृह व पंचकर्म सेंटर का लोकार्पण तथा महिला छात्रावास का शिलान्यास के अवसर पर बोल रही थी। राष्ट्रपति ने वन महोत्सव के अंतर्गत यहां भी रुद्राक्ष का पौधा रोपा, फिर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि नए महिला छात्रावास का शिलान्यास कर सबसे अधिक खुशी हो रही है। शिक्षा ही सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है, इसलिए यह कदम नारी सशक्तिकरण की दिशा में अमूल्य पहल है।

राष्ट्रपति ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की सराहना करते हुये कहा कि महाराणा प्रताप के आदर्शों से प्रेरित सभी संस्थानों में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना प्रसारित होती है। लगभग 700 वर्ष पहले महाराणा प्रताप ने राष्ट्रगौरव के लिए त्याग और पराक्रम का जो आदर्श प्रस्तुत किया था, वह देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। उन्होने आशा जताई कि इस विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थी प्रोफेशनल एजुकेशन पर आधारित उत्कृष्टता प्राप्त करने के साथ-साथ आध्यात्मिकता तथा राष्ट्रप्रेम के आदर्शों को अपने आचरण में ढालेंगे।

उन्होने कहा कि मानव शरीर को दोषमुक्त बनाने में पंचकर्म की प्रक्रिया बहुत प्रभावी सिद्ध हुई है। इस क्रिया की सहायता से असाध्य रोगों के सफल उपचार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। आशा है कि नए पंचकर्म केंद्र से अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो पाएंगे।

राष्ट्रपति ने कहा " कक्षा सात की पढ़ाई पूरी करके मैं सत्र 1970-71 में आठवीं व उसके आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने गांव से 300 किमी. दूर भुवनेश्वर गई। 55 वर्ष पहले वह दूरी भी बहुत अधिक थी, क्योंकि तब आवागमन के साधन बहुत सीमित हुआ करते थे। मुझसे पहले मेरे गांव की कोई बालिका बाहर पढ़ने नहीं गई थी। भुवनेश्वर में मुझे महिला छात्रावास में रहने की सुविधा मिली। अब तो बहुत बदलाव आ चुका है। हमारी बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के नए प्रतिमान स्थापित कर रही हैं, लेकिन आज भी अनेक बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बेटियों के लिए सुरक्षित आवास न होने से उनकी उच्च शिक्षा की यात्रा में अवरुद्ध होता है।"

राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत परोपकार व जनहितैषी लक्ष्यों के लिए कार्य करने में निजी उच्च शिक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गोरखपुर व आसपास के क्षेत्र में उच्च शिक्षा में योगदान देने वाला यह पहला निजी विश्वविद्यालय है। उच्च शिक्षा में अग्रणी योगदान के लिए मैं गोरक्षपीठ व महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की सराहना करती हैं।

श्रीमती मुर्मू ने कहा कि पूर्ववर्ती राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था। केवल चार वर्ष में विश्वविद्यालय ने विकास यात्रा में प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की हैं। यह संस्थान पूर्वी उप्र में उच्च शिक्षा एवं रोजगारपरक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया है। इस विकास यात्रा में मुख्यमंत्री, विश्वविद्यालय के संस्थापक, कुलाधिपति योगी आदित्यनाथ का अमूल्य दिशानिर्देश व संबल उपलब्ध रहा है। विश्वविद्यालय की उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति ने योगी जी व पूरी टीम को बधाई दी। उन्होने कहा कि जब पूर्वांचल और अधिक स्वस्थ-सुरक्षित होगा, तब पूरा यूपी और तेजी से समग्र प्रगति के मार्ग पर बढ़ेगा। जब देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ेगा तो तब पूरा भारत प्रगति के नए प्रतिमान स्थापित करेगा।

दिल्ली में 5 दिन का अलर्ट यूपी से बिहार तक 10 राज्यों में भारी बारिश

✷ एनसीआर टुडे. नई दिल्ली ✷

दिल्ली में मानसून के पहुंचने के बाद अगले 5 दिन तेज बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट है। पहाड़ी राज्यों पर भारी बारिश का दौर जारी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश हो सकती है।

वहीं आंध्र प्रदेश और यनम में गर्म और आर्द्र मौसम रहने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में मानसून ने दश्तक दे दी है और पूरे देश को कवर कर लिया है। ऐसे में देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश का दौर जारी है। दिल्ली में भी लगातार हो रही बारिश हो रही है। यहां तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की ओर से दिल्ली के लिए बारिश का अलर्ट है और अगले 5 दिन दिल्ली में तेज बारिश होने की संभावना है। दिल्ली वालों को भीषण गर्मी से राहत मिली हुई है। मौसम सुहाना बना हुआ है। मानसून के दिल्ली में पहुंचने के बाद बारिश के साथ आंधी-तूफान और तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट है।

दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान है। सोमवार को जून का सबसे कम न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की ओर से दोनों ही राज्यों में आगे भी भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है।

अगले 7 दिनों के दौरान कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों, गुजरात राज्य में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। 2 से 5 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है।

52 उपग्रहों के प्रक्षेपण की प्रक्रिया को तेज करेगा भारत, सशस्त्र बलों के लिए जरुरी

✷ एनसीआर टुडे. नई दिल्ली ✷

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन के इलाके की 'गहरी' और 'लगातार' निगरानी के कारण भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा था।

इस सैन्य टकराव के दौरान देश को बहुत कुछ सीखने को भी मिला। इसी सीख को ध्यान में रखकर दुश्मन के इलाके की सतत निगरानी की आवश्यकता को देखकर मोदी सरकार ने अपने सशस्त्र बलों के लिए 52 उपग्रहों के प्रक्षेपण की प्रक्रिया को तेज़ किया है।

बता दें कि भारत सरकार सशस्त्र बलों के लिए 52 समर्पित उपग्रहों की लांच प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। इस मिशन को रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (डीएसए) के नेतृत्व में क्रियान्वित किया जा रहा है और यह रक्षा मंत्रालय की इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (आईडीएस) के तहत संचालित हो रहा है।

बात दें कि स्पेस-बेस्ड सर्विलांस (एसबीएस) कार्यक्रम के तीसरे चरण को बीते वर्ष अक्टूबर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी थी। इसकी लागत 26,968 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के तहत इसरो द्वारा 21 और तीन निजी कंपनियों द्वारा 31 उपग्रहों का निर्माण और प्रक्षेपण किया जाना है।

उल्लेखनीय हैं कि इन उपग्रहों में से पहला उपग्रह अगले वर्ष अप्रैल तक प्रक्षेपित किया जाना है और सभी 52 उपग्रहों को 2029 के अंत तक अंतरिक्ष में तैनात किया जाएगा।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इन उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट (लीओ) और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में जल्दी से जल्दी भेजने के लिए समयसीमा को कम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिन तीन निजी कंपनियों को अनुबंध दिए गए हैं, उन्हें उपग्रह निर्माण की गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

बताया जा रहा है कि स्पेस-बेस्ड सर्विलांस के तीसरे चरण का उद्देश्य चीन और पाकिश्तान के बड़े हिस्सों के साथ-साथ हिंद महासागर क्षेत्र को भी कवर करना है, जिससे कम समय में निगरानी संभव हो सके और चित्रों की गुणवत्ता भी बेहतर हो।

रूस में आज कमीशन होगा आईएनएस तमाल, भारतीय नौसेना को मिलेगा नया स्टील्थ युद्धपोत

✷ एनसीआर टुडे. नई दिल्ली ✷। भारतीय नौसेना को आज एक और अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट मिलने जा रहा है। रूस के कालिनिनग्राद स्थित यांतर शिपयार्ड में आईएनएस तमाल को आज 1 जुलाई को भव्य समारोह में कमीशन किया जाएगा। इस अवसर पर पश्चिमी नौसेना कमान के कमांडर वाइस एडमिरल संजय जे. सिंह मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम में भारत और रूस के कई शीर्ष सरकारी व रक्षा अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आईएनएस तमाल एक मल्टी-रोल स्टील्थ फ्रिगेट है, जिसे भारत और रूस की संयुक्त साझेदारी में निर्मित किया गया है। इस युद्धपोत में 33 फीसदी स्वदेशी उपकरण शामिल हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आईएनएस तमाल को पश्चिमी नौसेना कमान के अधीन तैनात किया गया। यह जहाज अरब सागर और कराची के समीपवर्ती समुद्री क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा। अत्याधुनिक हथियारों और रडार सिस्टम से लैस यह फ्रिगेट भारतीय नौसेना की शक्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि करेगा।

नई खेल नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी, 2047 तक भारत को शीर्ष-5 खेल राष्ट्र बनाना लक्ष्य

✷ एनसीआर टुडे. नई दिल्ली ✷। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति (एनएसपी) 2025 को मंजूरी दे दी है। यह देश के खेल परिदृश्य को नया आकार देने और खेलों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल है। नई खेल नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। ये भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने तथा 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्टता के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए एक दूरदर्शी और रणनीतिक रोडमैप प्रस्तुत करेगी।

कावड़ यात्रा के संबंध में उप्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विहिप ने की सराहना

✷ एनसीआर टुडे. नई दिल्ली ✷। विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) के केन्द्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ सुरेन्द्र जैन ने कावड़ यात्रा के संबंध में उप्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की है। जैन ने कहा कि राष्ट्रीय एकता, समरसता और एकात्मता की प्रतीक इस यात्रा का सभी मत-पंथ संप्रदाय व धर्मों के लोगों को ना सिर्फ खुले मन से स्वागत करना चाहिए अपितु, कावड़ यात्रियों के संवैधानिक अधिकारों की भी रक्षा करनी चाहिए। जैन ने आगे कहा कि लगभग 8 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष इस पवित्र यात्रा में भाग लेते हैं। यह यात्रा आस्था के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता, समरसता और एकात्मता का प्रतीक बन चुकी है।डॉ सुरेन्द्र जैन ने कहा कि इस यात्रा का समाज के सभी वर्गों के द्वारा भरपूर स्वागत होना चाहिए। यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं जुटानी चाहिए लेकिन दुर्भाग्य से हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक के राश्ते में कई बार इन यात्रियों पर हमले होते थे, जान से मार दिया जाता था।

ईडी ने घर खरीदारों के साथ 'धोखाधड़ी' में 'रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड' के परिसरों पर छापे मारे

✷ एनसीआर टुडे. नई दिल्ली ✷। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन के एक मामले में रियल एस्टेट कंपनी 'रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड' और उसके निदेशकों के खिलाफ छापेमारी में संपत्तियों का ब्योरा मिला है और 'अभियोजनयोग्य' दश्तावेज जब्त किये गये हैं। यह छापेमारी दिल्ली-एनसीआर तथा पंजाब के मोहाली में 27 जून को की गयी थी।

जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली करे, पांच प्रमुख हस्तियों ने सीजेआई को लिखा खुला पत्र

सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने का आग्रह

✷ एनसीआर टुडे. नई दिल्ली ✷

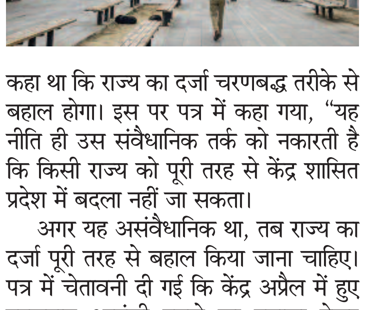

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली में हो रही देरी पर पांच प्रमुख हश्तियों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई को खुला पत्र लिखकर स्वतः संज्ञान लेने और मुद्दे पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने का आग्रह किया है।

इस पत्र पर हश्ताक्षर करने वालों में पूर्व केंद्रीय गृह सचिव गोपाल पिल्लई, जम्मू-कश्मीर के लिए वार्ताकार समूह की पूर्व सदस्य राधा कुमार, भारतीय सेना के सेवानिवृत्त मेजर जनरल अशोक के मेहता, भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल कपिल काक और अंतर-राज्यीय परिषद के पूर्व सचिव अमिताभ पांडे शामिल हैं।

इन सभी ने सामूहिक पत्र में लिखा है, राज्य का दर्जा समाप्त कर दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदलना संविधान के खिलाफ है। भारत एक संघीय लोकतंत्र है, जहां राज्यों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप पत्र का स्वतः संज्ञान लें और इस मुद्दे की सुनवाई के लिए एक पीठ गठित करें ताकि राज्य का दर्जा बहाल हो सके और भविष्य में किसी राज्य का दर्जा खत्म न हो सके। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने नवंबर 2019 में संसद में राज्य का दर्जा शीघ्र बहाल करने का वादा किया था जो अब तक अधूरा है।

पत्र में बताया गया कि दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि राज्य का दर्जा चरणबद्ध तरीके से बहाल होगा। इस पर पत्र में कहा गया, "यह नीति ही उस संवैधानिक तर्क को नकारती है कि किसी राज्य को पूरी तरह से केंद्र शासित प्रदेश में बदला नहीं जा सकता।

अगर यह असंवैधानिक था, तब राज्य का दर्जा पूरी तरह से बहाल किया जाना चाहिए। पत्र में चेतावनी दी गई कि केंद्र अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले का हवाला देकर बहाली में देरी को जायज ठहरा सकती है, जबकि हकीकत में यह बहाली का बिल्कुल उचित समय है। उन्होंने लिखा, अक्टूबर 2024 में हुए विधानसभा चुनावों में भारी मतदान और क्षेत्रीय पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली स्पष्ट बहुमत ने स्पष्ट किया है कि जनता ने एक चुनी हुई मजबूत सरकार को वोट दिया है।" उन्होंने बताया कि नई विधानसभा ने पहली बैठक में ही राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रश्ताव पारित किया और राज्यपाल मनोज सिन्हा के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया, लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पत्र में पहलगाम हमले के बाद कश्मीरियों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों पर चिंता जाहिर किया गया।

दिव्यांशी ने ताशकंद में अंडर-15 एशियाई युवा चैंपियन का खिताब जीता

✷ वेबवार्ता. कोलकाता ✷

दूसरी वरीयता प्राप्त क दिव्यांशी भौमिक ने ताशकंद के हुमो एरिना में आयोजित 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप 2024 में अंडर-15 गर्ल्स सिंगल्स में चीन की झू किही को 4-2 से हराकर स्वर्ण पदक के साथ यादगार जीत दर्ज की। नॉकआउट चरण में चीनी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अपनी दूसरी जीत के साथ दिव्यांशी ने न केवल खुद को एशियाई चैंपियन का खिताब दिलाया, बल्कि नवंबर में रोमानिया में होने वाली विश्व युवा चैंपियनशिप के लिए सीधे स्थान भी हासिल किया। उनके स्वर्ण पदक ने चैंपियनशिप में भारत के शानदार अभियान का समापन किया, जिसमें एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक शामिल थे।

सात गेम के कड़े सेमीफाइनल में लियू जिलिंग को हराने के बाद, आत्मविश्वास से भरी दिव्यांशी ने किही के खिलाफ मजबूत शुरुआत की और अपने तीसरे गेम पॉइंट पर पहला गेम जीत लिया। उसने अपनी गति बनाए रखी और 2-1 से आगे हो गई, हालांकि किही ने वापसी करते हुए बराबरी हासिल कर ली। इससे विचलित हुए बिना, भारतीय खिलाड़ी ने अपनी सर्विस और सामरिक विविधता को बढ़ाया और 3-1 से बढ़त हासिल कर ली। चीनी पैडलर ने पांचवें गेम में वापसी की और दिव्यांशी के 9-9 से बराबरी करने के बावजूद 11-9 से गेम अपने नाम कर लिया। लेकिन छठे गेम में, मुंबई की लड़की ने 6-2 से बढ़त हासिल कर ली, लेकिन किही ने अंतर को 8-8 पर ला दिया। अपने धैर्य को बनाए रखते हुए, दिव्यांशी ने चतुराई से सर्विस और रिटर्न पर गति को बदला और मैच को 13-11, 11-8, 8-11, 12-10, 9-11, 11-8 से अपने नाम कर लिया। सेमीफाइनल में दिव्यांशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चीन की जिलिंग लियू को 4-3 से हराया और फाइनल में अपनी जगह पक्की की।

अब टिकट कैंसल या वेटिंग होने पर नहीं कटेगा चार्ज, पूरा मिलेगा रिफंड

रेलवे क्लर्क फीस खत्म करने पर कर रहा विचार, यात्रियों को मिलेगी राहत

✷ एनसीआर टुडे. नई दिल्ली ✷

यात्रियों को रेलवे अब बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहा है। यदि कोई टिकट बुक करता है और वह वेटिंग में दिखा रहा है तो कैंसल होने के बाद भी पूरा रिफंड नहीं मिलता है। इसकी वजह होती है कि रेलवे क्लर्क फीस के तौर पर कुछ पैसा काट लेता है।

यह चार्ज अलग-अलग क्लास के मुताबिक 30 से 60 रुपए तक होता है। इससे यात्रियों डबल झटका लगता है। एक तरफ उनका टिकट कन्फर्म नहीं होता तो दूसरी तरफ रिफंड भी कटकर मिलता है। अब ऐसी स्थिति से लोगों को बचाने के लिए रेलवे इस फीस को खत्म करने पर विचार कर रहा है।

कैंसल टिकटों पर भी लगने वाले चार्ज पर लंबे समय से बहस चल रही है। अलग-अलग क्लास के हिसाब से यह चार्ज 30 से 60 रुपए कटता है। इस पर आम लोग कई बार शिकायत करते रहे हैं कि आखिर जिन टिकटों को हम खुद कैंसल नहीं कराते और वेटिंग सूची में होने के चलते रद्द होते हैं, उन पर रेलवे क्यों पैसा काटता है। अब इस चार्ज को खत्म करने का प्रश्ताव रेलवे के समक्ष रखा गया है, जिस पर विचार चल रहा है। फिलहाल 2एस क्लास के कैंसल टिकट 30 रुपए का चार्ज लगता है। 60 रुपए स्लीपर क्लास का चार्ज है और थर्ड एसी समेत अन्य सभी पर 60 रुपए प्लस जीएसटी वसूला जाता है। यह फीस तब लगती है, जब टिकट की बुकिंग आईआरसीटीसी के पोर्टल से की जाए। वेटिंग सूची वाला टिकट कन्फर्म न होने पर टिकट कैंसलेशन की प्रक्रिया ऑटोमेटेड होती है और क्लर्क चार्ज के अलावा कुछ अन्य शुल्क काटकर रकम वापस मिलती है। बता दें फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेलवे को रिकॉर्ड 2.7 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है। यह इजाफा मालवाहक ट्रेनों और यात्री ट्रेनों से हुआ है। इसके अलावा रेलवे के यात्रियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। रेलवे को माल ढुलाई से 1.75 लाख करोड़ का राजस्व मिला। इसके अलावा य़ात्रियों की संख्या 735 करोड़ रही।

बता दें रेलवे को टिकट कैंसलेशन चार्ज से भी बड़ा राजस्व मिलता है। एक आरटीआई के जवाब में दी गई जानकारी से पता चला कि रेलवे ने 2020 से 2023 के दौरान 4 सालों में अकेले टिकट कैंसलेशन चार्ज से ही 6 हजार करोड़ का राजस्व हासिल किया। इस डेटा के सामने आने के बाद से वेटिंग सूची टिकट के कैंसल होने पर कटने वाले चार्ज को लेकर सवाल उठने लगे थे।

गरीबों को दंडित करने का प्रावधान है मोदी सरकार का जीएसटी : राहुल

✷ एनसीआर टुडे. नई दिल्ली ✷

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वश्तु एवं सेवा कर-जीएसटी को जनता के साथ आर्थिक अन्याय और गरीबों को दंडित करने वाला प्रावधान करार देते हुए कहा है कि यह जीएसटी महज कारपोरेट भाई भतीजावाद तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है।

श्री गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में जीएसटी के आठ साल पूरा होने पर कहा "आठ साल बाद, मोदी सरकार का जीएसटी कोई कर सुधार नहीं है - यह आर्थिक अन्याय और कॉर्पोरेट भाई-भतीजावाद का एक क्रूर साधन है। इसे गरीबों को दंडित करने, एमएसएमई को कुचलने, राज्यों को कमजोर करने और प्रधानमंत्री के कुछ अरबपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया था। एक 'अच्छा और सरल कर'बनाने का वादा था लेकिन देश की जनता को जीएसटी के रूप में दुःस्वप्न मिला जिसमें पाँच-स्लैब हैं और अब तक इसमें 900 से अधिक बार संशोधन किया गया है। यहाँ तक कि कारमेल पॉपकॉर्न और क्रीम बन भी इसके भ्रम में फँस गए हैं।"

उन्होंने कहा कि नौकरशाही बड़े कॉरपोरेट्स के पक्ष में है और वे इसकी खामियों को एकाउंटेंट की सेना के साथ दूर कर सकते हैं, जबकि छोटे दुकानदार, एमएसएमई और आम व्यापारी लालफीताशाही में फंसे हुए हैं और जीएसटी पोर्टल दैनिक उत्पीड़न का स्रोत बना हुआ है। इससे देश के सबसे बड़े रोजगार सृजक एमएसएमई को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा है।

संक्षिप्त समाचार

सिगरेट पीने से मना किया तो घर में घुसकर चेन लूट ली, गाजियाबाद में तो गजब कांड हुआ

गाजियाबाद एजेंसी। गाजियाबाद के गुलधर में घर के सामने बाइक खड़ी कर सिगरेट पीने से मना करने पर आरोपी ने युवक से पहले गाली गलौज की, फिर दोस्तों को बुलाकर उनके घर में घुसकर मारपीट की। इस दौरान उनकी सोने की चेन और नकदी भी लूटकर ले गए। पीड़ित ने मधुबन बापूधाम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार,गुलधर के रहने वाले मनीष त्यागी ने शिकायत में बताया कि एक मई की रात उनके घर के बाहर संजयनगर निवासी दिलीप बाइक लगाकर शराब के नशे में सिगरेट पी रहा था। उन्होंने उससे वहां से बाइक हटाने के लिए कहा,तो उसने गाली गलौज की। विरोध करने पर आरोपी ने फोन कर अपने दोस्तों को बुला लिया। आरोप है कि दस मिनट में उसके सात से आठ दोस्त स्कूटी और बाइक से आ गए और उनके साथ गाली गलौज करने लगे।पीड़ित अपने घर चला गया तो सभी आरोपी उनके घर पहुंच गए और हमला कर दिया। आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने पीड़ित की सोने की चेन और 1500 रुपये भी लूट लिए। इसकी शिकायत थाने देने पर आरोपी फिर उनक घर के सामने पहुंचकर जान से मारने की धमकी दी। एसीपी का कहना है कि शिकायत के बाद मामले की जांच की जा रही है।

न वैक्सीन लगवाई, न इलाज; मां-बाप के अंधविश्वास में एक साल के मासूम की पीलिया से मौत

मलप्पुरम, एजेंसी। केरल के मलप्पुरम जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक साल के मासूम बच्चे की पीलिया से मौत हो गई और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच मां-बाप के अंधविश्वास के तौर पर कर रही है। संदेह जताया जा रहा है कि बच्चे को समय पर दवाई नहीं दी गई, क्योंकि उसके माता-पिता एलोपैथिक इलाज के खिलाफ थे। मृतक बच्चे का नाम एसन एरहान था, जो कोट्टक्कल के रहने वाले हिरा हरीरा और नवाज का बेटा था। बच्चे की 27 जून को मृत्यु हो गई थी और प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि उसका न तो टीकाकरण हुआ था और न ही पीलिया के इलाज के लिए कोई इलाज हुआ। हैरानी की बात यह है कि बच्चे की मां एक्यूपंक्चर की चिकित्सक हैं और उन्होंने पहले भी सोशल मीडिया पर मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ पोस्ट की थीं, जो अब वायरल हो रही हैं और चर्चा का विषय बन गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम जब घर पहुंची, तो परिवार ने बताया कि बच्चा स्तनपान के तुरंत बाद बेहोश हो गया और उसकी मौत हो गई। हालांकि, टीकाकरण न कराना और अस्पताल न ले जाना अधिकारियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। बच्चे का पोस्टमार्टम के लिए शव बाहर निकाला गया है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

भारत सरकार लिखी गाड़ी, जमकर रौब, मुंबई से फर्जी आईएएस अधिकारी गिरफ्तार

मुंबई, एजेंसी। मुंबई पुलिस ने भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी के फर्जी दस्तावेज लेकर घूमने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी खुद को आईएएस अधिकारी बताकर कस्टम गेस्ट हाउस में रुका था। इतना ही नहीं वह भारत सरकार की नेम प्लेट वाली गाड़ी का भी इस्तेमाल करता था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को जब इस घटनाक्रम का पता चला तो शनिवार को उसे मलाड इलाके में एक होटल के बाहर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान बिहार निवासी 32 वर्षीय चंद्रमोहन सिंह के रूप में हुई है। गिरफ्तार करने के दौरान उसने अपने आप को गृह मंत्रालय से संबंधित बताते हुए उसने एक फर्जी पहचान पत्र भी दिखाया। बाद में जब सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया और उसने दस्तावेजों के जाली होने की बात को कबूल कर लिया।

पुलिस को उसके पास से रक्षा मंत्रालय से जुड़े फर्जी दस्तावेज भी मिले हैं पुलिस ने बताया पकड़े जाने से पहले यह आरोपी दादर में नाके से भागने में भी सफल रहा था। यहां पर उसने पुलिस कांस्टेबल ने जब उसे ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने के लिए रोका तो उसने अपने आप को आईएएस अधिकारी बताया और वहां से निकल गया। अधिकारी के अनुसार, पुलिस फिलहाल उसे गिरफ्तार करके उसके खिलाफ संबंधित मामलों में केस दर्ज कर रही है।

नियुक्ति राजस्थान सरकार के लिए बनीं अग्निपरीक्षा 10 हजार से ज्यादा पद न्यायिक प्रक्रिया में फंसे

जयपुर, एजेंसी।
राजस्थान में बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार जल्द ही प्रदेश भर में मेगा रोजगार मेलों का आयोजन करने जा रही है। दावा है कि इन मेलों के जरिए 20 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया जाएगा। अगर कोर्ट में अटकी भर्तियों के मामले सुलझ जाते हैं, तो यह संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद भी हाल ही में एक कार्यक्रम में इस योजना का संकेत दे चुके हैं।

फिलहाल 8 अहम भर्तियां ऐसी हैं जो या तो कोर्ट में अटकी हुई हैं या फिर विभागीय लापरवाही की शिकार हैं। इनमें से 4 भर्तियों पर कानूनी पेच फंसा हुआ है, जबकि 4 भर्तियों की प्रक्रिया अधिकारी स्तर की अनदेखी के कारण धीमी पड़ी हुई है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हनुमान किसान का कहना है कि सरकार को कोर्ट में ठोस पैरवी करनी चाहिए, ताकि चयनित अभ्यर्थियों को जुलाई में नियुक्ति पत्र सौंपे जा सकें। पशु परिचर भर्ती 2023 (6433 पद) इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन को लेकर विवाद है, जो कोर्ट में लंबित है। इसी कारण चयन प्रक्रिया रुकी हुई है।

इस भर्ती में कुछ सवालों को लेकर विवाद है, जिस पर कोर्ट का फैसला आना बाकी है। ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया लंबित है।

इस भर्ती में पहले से कार्यरत डिप्टीशनी कार्मिकों ने कोर्ट में चुनौती दे रखी है, जिससे चयनित अभ्यर्थियों की राह अटक गई है। विवादित प्रश्नों के चलते कोर्ट में मामला चल रहा है। करीब 713 पदों पर अभी भी नियुक्तियां नहीं हो सकी हैं। लेवल-2 में दो गुणा परिणाम जारी हो चुका है, लेकिन उर्दू को छोड़कर अन्य विषयों का एक गुणा परिणाम अब तक लंबित है। इससे करीब 1260 नए अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है।600 पदों में से 120 पदों का परिणाम अब तक जारी नहीं किया गया है। चयनित अभ्यर्थी लगातार परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। 13 मई को चयन बोर्ड ने परिणाम तो जारी किया, लेकिन शिक्षा विभाग ने अब तक दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम घोषित नहीं किया।

राजा रघुवंशी की हत्या के बाद बदला नियम, मेघालय सरकार ने कड़े किए नियम

शिलांग, एजेंसी।
मेघालय के अधिकारियों ने पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर पूर्वी खासी पवर्तीय जिले में बाहरी इलाकों के लिए गाइड रखना अनिवार्य कर दिया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। यह आदेश इंदौर के व्यापारी राजा रघुवंशी की हत्या के एक महीने बाद आया है, जिसकी योजना उनकी पत्नी ने राज्य के सोहरा क्षेत्र में अपने हनीमून के दौरान बनाई थी। पूर्वी खासी पवर्तीय जिले की उपायुक्त रोसेटा एम कुरबाह ने आदेश में कहा, 'सुरक्षा कारणों को देखते हुए, अब सभी पर्यटकों के लिए क्षेत्र में पर्वतारोहण के दौरान रजिस्टर्ड गाइड की सेवाएं लेना जरूरी है।' इससे अलग-थलग क्षेत्रों में खो जाने, चोट लगने या आपराधिक गतिविधियों का शिकार होने जैसी घटनाओं को रोकने में भी मदद मिलेगी। कुरबाह जिला पर्यटन संवर्धन सोसाइटी की अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला दिया। उक्त घटना की पूरे देश में चर्चा हो रही है और मामले में मध्यप्रदेश के इंदौर से आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पर्यटन अधिकारियों ने कहा कि आदेश का सख्ती से पालन किया जाएगा। उल्लंघन करने वालों को जुर्माना भरना पड़ सकता है या उन्हें विभिन्न मार्गों पर जाने से रोका जा सकता है। प्रशासन ने निर्देश को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अधिक ट्रेंड गाइड तैनात करने और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करने की भी योजना बनाई है। इससे पहले, मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीमने रविवार को अहम सफलता हासिल करते हुए राजा रघुवंशी की गुम हुई सोने की चेन समेत कई अहम सबूत बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स के मध्यप्र देश के रतलाम जिले में स्थित आवास पर छापेमारी के दौरान यह बरामदगी की गई। इस अभियान में राजा और उसकी पत्नी सोनम के सोने के आभूषण, लैपटॉप और अन्य सामग्री जब्त की गई।

यूपी में जहां-तहां कचरा फेंकने वाले रहें सावधान, अब कई विभागों की आप पर नजर, लगाएंगे तगड़ा जुर्माना

कानपुर, एजेंसी।
यूपी में गंगा ही नहीं अब गलियों तक में कूड़ा फेंकना दंडनीय अपराध होगा। ऐसा करने पर आपको 50,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। यह निर्देश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने ओरीजिनल अप्लीकेशन (ओए) पर सुनवाई के दौरान दिया है। एनजीटी के आदेश के अनुपालन में उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने सख्ती का फरमान जारी किया है। यूपीपीसीबी के अलावा नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के अधिकारी जुर्माना लगाने की कार्रवाई कर सकेंगे।

एनजीटी ने राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य के प्रकरण की बीते दिनों सुनवाई की। एनजीटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यूपी की किसी भी नदी, झील, तालाब, वेटलैंड के अलावा पीडब्ल्यूडी और राजस्व भूमि पर कचरा फेंकना दंडनीय अपराध होगा। कचरा फेंकने वाले व्यक्ति पर पर्यावरणीय क्षति के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। एनजीटी ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 30 जुलाई मुकर्रर की है। 9 जुलाई तक आदेश के अनुपालन में यूपीपीसीबी को आख्या दाखिल करनी है। क्षेत्रीय अधिकारी यूपीपीसीबी 7 जुलाई तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी को अपनी आख्या भेजेंगे।

गलियों या जलाशय में कचरा फेंकने पर पहली बार 5000 रुपये जुर्माना लगेगा। दूसरी बार कूड़ा फेंकते पकड़े जाने पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगेगा। जुर्माने की इस कार्रवाई के दायरे में खासकर वह लोग आएंगे, जो घर के बाहर सड़क या पार्कों में कूड़ा फेंकने के आदी हैं। घर का कचरा या मलबा बड़ी मात्रा में फेंकने वालों पर पर्यावरणीय क्षति की दर अलग तय की गई है। ऐसे लोगों पर पहली बार कचरा फेंकने पर 25000 रुपये की वसूली होगी। दूसरी या इससे अधिक बार कचरा फेंकते पाए जाने पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। जुर्माने की राशि जमा न करने पर राजस्व विभाग आरसी का नोटिस जारी करेगा। आरसी जारी होने पर भी जुर्माना न भरने पर विधिक कार्रवाई होगी। एनजीटी ने कहा है कि वसूली गई राशि का प्रयोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में किया जाएगा। ताकि, पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जा सके। गंगा में कूड़ा फेंकने पर अभी नगर निगम 2500 रुपये तक जुर्माना लगाता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नेशनल एक्ट में 5000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अफसर व नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमित सिंह गौर ने बताया कि नगर निगम सदन ने कूड़ा फेंकने पर 2500 की दर तय की थी। कूड़ा फेंकने पर कई लोगों से वसूली भी की जा चुकी है।

यूपीपीसीबी के आरओ अजीत कुमार सुमन ने कहा बताया कि सदस्य सचिव यूपीपीसीबी ने एनजीटी के आदेश के अनुपालन के निर्देश दिए हैं। अब गंगा ही नहीं गलियों में भी कूड़ा फेंकने पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। पीसीबी के अलावा स्थानीय निकाय को भी कार्रवाई का अधिकार है।

कर्नाटक में सीएम बदलने पर रार तेज, शिवकुमार गुट बोला- 100 एमएलए साथ, हाईकमान ने भेजा दूत

बेंगलुरु, एजेंसी।
कर्नाटक में सीएम बदलने की मांग फिर से जोर पकड़ रही है और इस बार तो मामला दिल्ली दरबार तक जा पहुंचा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को ही इसका संकेत दिया था। इस बीच दिल्ली से आए प्रतिनिधि के तौर पर रणदीप सुरजेवाला ने कर्नाटक के कई विधायकों से मुलाकात की है। फिलहाल सोनिया और राहुल गांधी चाहते हैं कि विधायक शांत हो जाएं और खींचतान सार्वजनिक तौर पर न दिखे। वहीं डीके शिवकुमार के समर्थक अब आर-पार के मूड में दिख रहे हैं। कर्नाटक में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी। इस इलेक्शन के बाद चर्चा थी कि डीके शिवकुमार सीएम होंगे, लेकिन सिद्धारमैया को मौका मिला।

किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा था, लेकिन तब से ही डीके शिवकुमार के समर्थक दोहरा रहे हैं कि सिद्धारमैया को ढाई साल के लिए ही सीएम बनाया गया है। इसी के चलते अब वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। इस बीच डीके शिवकुमार के करीबी विधायक इकबाल हुसैन ने बड़ा दावा किया है। हुसैन का कहना है कि करीब 100 कांग्रेस विधायक डीके शिवकुमार के साथ हैं और ये सभी लोग अब मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें देखना चाहते हैं। हम सभी की मांग है कि अब बदलाव हो जाए। यही नहीं उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शिवकुमार को सत्ता नहीं सौंपी गई तो फिर कांग्रेस 2028 में वापसी नहीं कर पाएगी।

शिवकुमार के करीबी ने कहा कि मैं इस बारे में दिल्ली से आए रणदीप सुरजेवाला से भी बात करूंगा। उन्होंने कहा कि यदि अभी बदलाव नहीं हुआ तो फिर देर हो जाएगी। पार्टी के हित में है कि शिवकुमार को अब सत्ता दी जाए। दरअसल मल्लिकार्जुन खरगे ने बढ़ते विवाद को लेकर सोमवार को कहा था कि इस बारे में कोई फैसला पार्टी हाईकमान ही ले सकता है। इस पर हुसैन ने कहा कि हमने तो हमेशया ही हाईकमान का सम्मान किया है। पार्टी में अनुशासन भी है। लेकिन हम हर बात हाईकमान को बताएंगे। कर्नाटक के बारे में सारे तथ्य उनके आगे रखेंगे। कर्नाटक में डीके शिवकुमार के समर्थक विधायक ऐक्टिव हैं, लेकिन सीएम सिद्धारमैया सब नॉर्मल दिखाने की कोशिश में हैं। उन्होंने मीडिया के सवालों पर कहा कि सिद्धारमैया के साथ कोई मतभेद नहीं हैं।

गुरुग्राम-सोहना हाईवे दो साल में पांचवीं बार धंसा

गुरुग्राम , एजेंसी। गुरुग्राम-सोहना हाईवे एक बार फिस से धंस गया। पिछले दो साल में यह पांचवीं बार धंसा है। इस बार सड़क में करीब चार मीटर चौड़ा गड्ढा होने की सूचना है। गनीमत रही कि धंसे हिस्से के ऊपर अभी सड़क का निर्माण नहीं हुआ था। गत 18 जून को भी गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर रहेजा मॉल के पास एक गड्ढा हो गया था।

इसकी सूचना मिलने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा इस हाईवे की बैरिकेडिंग कर दी गई। जीएमडीए ने 19 जून से इस हाईवे के नीचे से निकल रही सीवर लाइन को दुरुस्त करने का काम शुरू किया। 27 जून को सीवर लाइन दुरुस्त किया गया। 28 जून को जीएमडीए ने एनएचएआई को सूचित किया कि सीवर लाइन की मरम्मत कर दी गई है। अभी हाईवे निर्माता कंपनी की तरफ से हाईवे के इस क्षतिग्रस्त हिस्से को दुरुस्त करने की योजना बनाई जा रही थी कि सोमवार शाम को इस हिस्से के दोबारा धंसने की सूचना सामने आ गई। इस बार सड़क के इस हिस्से में करीब चार मीटर चौड़ा गड्ढा हो गया। एनएचएआई ने जीएमडीए को इसकी जानकारी दे दी है। जीएमडीए ने सीआईपीपी (क्यूरड इन प्लेस पाइप) पद्धति से इस सीवर लाइन की मरम्मत करने की योजना बनाई थी। इसके तहत पिछले साल नवंबर माह में 19.31 करोड़ रुपये का टेंडर लगाया था। सीआईपीपी करने वाली कंपनियों के कम होने के कारण इस टेंडर के तहत दो कंपनियों ने आवेदन किया था। राकेश भारद्वाज, पदाधिकारी, हाईवे निर्माता कंपनी, जीएमडीए की क्षतिग्रस्त सीवर लाइन की वजह से कभी भी हादसा हो सकता है। दो दिन पहले जीएमडीए अधिकारियों ने सूचना दी थी कि क्षतिग्रस्त सीवर लाइन को दुरुस्त कर दिया है। अभी तो सड़क का निर्माण करना शुरू नहीं किया था तो हाईवे का बहुत बड़ा हिस्सा धंस गया। इसकी वजह से बड़ा हादसा हो सकता है। योगेश तिलक, परियोजना अधिकारी, एनएचएआई, पांचवीं बार गुरुग्राम-सोहना हाईवे पर रहेजा मॉल के पास सीवर की लाइन क्षतिग्रस्त हुई है। जीएमडीए को सूचना दे दी है। उनसे आग्रह किया है कि सीवर लाइन को दुरुस्त करवाया जाए।

नए नोएडा का जमीन अधिग्रहण सर्किल रेट लागू न होने से अटका

नोएडा एजेंसी।
गौतमबुद्ध नगर के नए सर्किल रेट दो महीने पहले तय हो चुके हैं, लेकिन उन्हें लागू करने का फैसला अब तक नहीं हो सका है। इसके चलते मुआवजे की दर तय नहीं पा रही है। इस कारण नए नोएडा के लिए जमीन अधिग्रहण की मुआवजा राशि भी प्रस्तावित नहीं हो सकी है। शासन ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जनवरी 2021 में दादरी-नोएडा गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र (डीएनजीआईआर) यानी नए नोएडा की घोषणा की थी। शासन ने नए शहर के लिए अक्टूबर 2024 में अधिसूचना जारी की थी और इसके विकास का जिम्मा नोएडा प्राधिकरण को सौंपा था। नोएडा प्राधिकरण इसके लिए होने वाले जमीन अधिग्रहण के लिए एक हजार करोड़ का बजट भी स्वीकृत कर चुका है, लेकिन अब तक अधिग्रहण तो दूर मुआवजा की दर भी प्रस्तावित नहीं हैं। नए नोएडा में गौतमबुद्ध नगर के अलावा बुलंदशहर के भी गांव शामिल हैं। जमीन के मुआवजे की दर दोनों ही जिलों के प्राधिकरण और प्रशासन के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में तय होनी है। इसके लिए पिछले लंबे समय से किसानों से वार्ता भी चल रही है, लेकिन मुआवजा दर घोषित नहीं हो सकी है। मुआवजे की दरें क्या रखी जाएं, इसके लिए प्राधिकरण की समिति अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि बोर्ड से जो दरें तय होंगी, उन पर किसानों से जमीन ली जाएगी। इसके लिए नए सर्किल रेट लागू होने का भी इंतजार है। नया नोएडा 20 हजार 911.29 हेक्टेयर में बसाया जाएगा। नोएडा की घोषणा होने के बाद से ही बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण शुरू हो गया है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दादरी बाईपास के आसपास अवैध कॉलोनियों बसने के साथ वेयर हाउस भी बन गए हैं।

ओडिशा में नगर निगम के अधिकारी संग मारपीट मामले में ऐक्शन, तीन हमलावर गिरफ्तार

भुवनेश्वर, एजेंसी।
ओडिशा प्रशासनिक सेवा के सीनियर अधिकारी और भुवनेश्वर नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त रत्नाकर साहू के साथ सोमवार को कुछ बदमाशों ने मारपीट की। पुलिस ने यह जानकारी दी। साहू ने खारवेलनगर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। भुवनेश्वर के डीसीपी जगमोहन मीना ने बताया, अधिकारी ने खारवेल नगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। हमने अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी ने कहा कि पुलिस ने अब तक जीवन राउत, रश्मि महापात्रा और देबाशीष प्रधान को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है। अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता का पता लगाया जा रहा है।

ओएएस अधिकारी पर हमले के विरोध में बीजद समर्थकों ने मुख्य सड़क जनपथ को जाम कर दिया। ओएएस एसोसिएशन ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिनकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। विपक्ष के नेता और बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी (जो गृह विभाग के भी प्रभारी हैं) से कहा कि वह अपनी सरकार में विश्वास बहाल करें। पूर्व राज्यपाल के बेटे की ओर से एक अधिकारी पर हमले की तरह इस जघन्य कृत्य के दोषियों दंडित किए बिना न जाने दें।

रिपोर्ट्स के अनुसार, 30 जून दोपहर 12:30 से 1:00 बजे के बीच, कुछ अज्ञात युवकों ने रत्नाकर साहू के चैंबर में जबरन प्रवेश किया। इनमें बीजेपी कॉरपोरेटर जीवान राउत भी शामिल थे। साहू द्वारा दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत के अनुसार, छह-सात अज्ञात व्यक्ति उनके दफ्तर में घुस आए और आक्रामक तरीके से पूछा कि क्या उन्होंने भुवनेश्वर के भाजपा नेता जगन्नाथ प्रधान से बात की है। साहू ने कहा कि उन्होंने जवाब दिया कि दिन में कुछ देर पहले प्रधान के साथ उनकी टेलीफोन पर बात हुई थी। जगन्नाथ प्रधान 2024 के विधानसभा चुनाव में हार गए थे।

इसके बाद समूह ने कथित तौर पर बिना किसी उकसावे के उन पर हमला करना शुरू कर दिया और मांग करते हुए कहा कि वे प्रधान से माफी मांगें। वे उनसे माफी की मांग क्यों कर रहे थे, यह स्पष्ट नहीं है। भीड़ ने उन्हें कॉलर से पकड़कर कार्यालय से बाहर घसीटा, थप्पड़ मारे, और चेहरे पर लात मारकर क्रूरता से पीटा। साहू ने यह भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने उन्हें जबरन एक वाहन में ले जाने की कोशिश की, जो अपहरण का प्रयास हो सकता था।

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साहू को घसीटते, पीटते और अपमानित करते हुए देखा जा सकता है। यह हमला करीब 25 मिनट तक चला, और सैकड़ों बीएमसी कर्मचारी और निजी सुरक्षा गार्ड मूकदर्शक बने रहे। अंततः, भुवनेश्वर की मेयर सुलोचना दास और पूर्व डिप्टी मेयर भारती सिंह ने हस्तक्षेप कर साहू को बचाया। साहू ने शिकायत में कहा, उन्होंने मुझे सार्वजनिक रूप से, जन प्रतिनिधियों यानी बीएमसी के पार्षदों, बीएमसी अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों की मौजूदगी में हत्या के प्रयास के साथ बेरहमी से पीटा। जब मैं खुद को बचाने और दया की भीख मांगने की कोशिश कर रहा था।

एनसीआर टुडे

विधायक ने पौधा लगाकर वन महोत्सव का शुभारंभ किया

✷ **एनसीआर टुडे. गाजियाबाद** ✷। कमला नेहरूनगर स्थित केंद्रीय विद्यालय में मंगलवार को वन महोत्सव का शुभारंभ हो गया। मुख्य अतिथि विधायक संजीव शर्मा ने पौधारोपण करके महोत्सव का श्रीगणेश किया। इस मौके पर मधुबनी चित्रकला कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। विजेताओं को विधायक ने प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म भी दिखाई गई। इस मौके पर क्षेत्रीय पार्षद प्रवीण चौधरी, सामाजिक वानिकी की प्रभागीय निदेशक ईशा तिवारी, एसडीओ डॉ सलोनी, आरएफओ निमी कुचिया आदि मौजूद रहे।

चोरी के सामान सहित पॉच अभियुक्त गिरफ्तार

✷ **एनसीआर टुडे. अलीगढ़** ✷। रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना

म हु आ खे ड़ा पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर बीएनएस में वांछित अभियुक्त कृष्णकांत सिंह उर्फ गोलू पुत्र हृदेश कुमार निवासी अम्बेडकर कालोनी रामघाट रोड थाना क्वार्सी अलीगढ़, सनी पुत्र सुभाष गुप्ता निवासी गाजीपुर थाना अतरौली अलीगढ़ हाल निवासी माली नगला धनीपुर मण्डी थाना गांधीपार्क अलीगढ़, प्रशान्त पुत्र हरप्रसाद निवासी गुरुसिकरन थाना हरदुआगंज अलीगढ़ हाल निवासी क्वार्सी चौराहा रामघाट रोड अलीगढ़, गौरव पुत्र विनोद कुमार निवासी आनन्द विहार कालोनी रामघाट रोड थाना क्वार्सी अलीगढ़ व दीपक उर्फ दीपा पुत्र रमेश चन्द्र निवासी होली चौक नगला थाना क्वार्सी अलीगढ़ को याकूतपुर पुलिया के सामने खाली प्लाट से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से एक इन्वर्टर, बैटरी, डीवीआर, एलईडी, 10 पेटी देशी शराब, चोरी की शराब बेचने से प्राप्त 4200 रुपये व घटना में प्रयोग टैम्पो नम्बर यू0पी0 81 ई0टी0 6452 सहित गिरफ्तार किया। पुलिस की इस कार्यवाही से आम जन मानस में प्रशंसा हो रही है।

तमंचा कारतूस सहित दो अभियुक्त गिरफ्तार

✷ **एनसीआर टुडे. अलीगढ़** ✷। जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा

रहे अभियान के क्रम में थाना म हु आ खे ड़ा पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर बीएनएस में वां छि त अभियुक्तगण अनीस पुत्र बन्ने खाँ निवासी गली नं0 01 शाहजमाल थाना रोरावर जनपद अलीगढ़ व लियाकत अली पुत्र मकसूद अली निवासी चामड़ के पास जलालपुर चौकी वाली गली थाना रोरावर जिला अलीगढ़ को चोरी के कुण्डल व एक तमंचा 315 बोर मय एक कारतूस 315 बोर सहित कृषि फार्म थाना क्वार्सी अलीगढ़ से गिरफ्तार किया।

बारिश से गिरी कमरे की छत, पति-पत्नी घायल

✷ **एनसीआर टुडे. अलीगढ़** ✷। खैर तहसील में दो दिन से जारी बारिश के कारण एक कमरे की छत गिर गई। इस

हादसे में कमरे में मौजूद पति-पत्नी घायल हो गए। घटना कीरतपुर में हुई, जहां मनोज अपने घर के कमरे में बैठा हुआ था। बारिश के कारण अचानक छत गिर गई। मनोज और उनकी पत्नी हेमा दोनों को चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैर में भर्ती कराया। मनोज की स्थिति अधिक गंभीर होने के कारण उन्हें अलीगढ़ मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया। पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश से क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गांवों में कच्चे मकानों में पानी भर जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

प्रत्येक सप्ताह कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने के दिए निर्देश

✷ **एनसीआर टुडे. अलीगढ़** ✷। डीएम संजीव रंजन द्वारा जिले में नकली कीटनाशक विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने, किसानों को गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक उपलब्ध कराने एवं नियमित निगरानी और कार्रवाई के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि कृषकों को गुणवत्ता युक्त कीटनाशक रसायन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, नकली, अमानक, अपंजीकृत व कीटनाशक अधिनियम 1968 के प्रावधानों का परिपालन कराने के लिए उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी एवं जिला कृषि रक्षा अधिकारी की तीन सदस्यीय जिला शतरीय स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो कि जिले की सभी तहसीलों में सघन निरीक्षण करेंगे। उन्होंने निर्देशित किया कि शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही कर प्रत्येक सप्ताह निरीक्षण आख्या अपर कृषि निदेशक (कृषि रक्षा) को ई-मेल adappup2018@gmail-com पर उपलब्ध करायेंगे।

नोएडा : 12 औद्योगिक प्लॉटों की योजना लाने की तैयारी

✷ **एनसीआर टुडे. नोएडा** ✷। लंबे इंतजार के बाद प्राधिकरण औद्योगिक प्लॉट की योजना ला रहा है। दिसंबर-2023 में औद्योगिक प्लॉट का आवंटन प्राधिकरण ने किया था। इसके बाद आवंटन पॉलिसी पर सवाल खड़े होने पर कोई योजना नहीं लाई गई थी। अब यूनिफाइड पॉलिसी के तहत 12 प्लॉटों की योजना आएगी। इनका आवंटन ई-नीलामी से होगा। आवेदक को ऑब्जेक्टिव परीक्षा पास करनी होगी। सेक्टर-7,8,10 व 80 में मौजूद प्लॉट 100 से लेकर 7500 वर्गमीटर के हैं।

MLA ने किया विशेष संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान का शुभारम्भ

✷ **एनसीआर टुडे. गाजियाबाद** ✷

जुलाई 2025 में प्रस्तावित विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के द्वितीय चरण की गतिविधियों हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र०, शासन के पत्र द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुपालन में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान (दिनांक 01-31 जुलाई, 2025) तथा दश्तक अभियान (दिनांक 11-31 जुलाई 2025), अभियान संचालित किया जाना है।

जिसका शुभारम्भ श्री अजीत पाल त्यागी जी, विधायक मुरादनगर द्वारा संयुक्त जिला चिकित्सालय, संजय नगर गाजियाबाद से रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना कर किया गया। संचारी रोगों के प्रति इस जागरूकता रैली में गुरूनानक इण्टर कॉलेज लोहिया नगर की एन०सी०सी० विंग एवं छात्रा बैड पार्टी, एम०बी० गर्ल्स इण्टर कॉलेज चन्दरपुरी की छात्रा टोली एवं शम्भु दयाल इण्टर कॉलेज की भारत स्काउट गाइड एवं एन०सी०सी० विंग की छात्रों ने पोस्टर, बैनर एच०एल०एम० कॉलेज के छात्रा, सन्तोष मैडिकल कॉलेज की छात्राओं ने प्रतिभाग किया। रैली में नगर निगम गाजियाबाद की लगभग छोटी बड़ी 100 फॉगिंग मशीन, 10 स्प्रीकलर एवं 05 पावर सप्रेयर मशीनों के साथ नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम गाजियाबाद डा० एम०के० सिंह भी उपस्थित रहें।

शुभारम्भ के समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजियाबाद डा० अखिलेश मोहन ने अपने सम्बोधन में रैली में उपस्थित समश्त प्रतिभागियों से जनपद में संचारी रोगों विशेषकर डेंगू से बचाव हेतु क्या करें क्या न करें की अपील की।

इस आयोजन में सिविल डिफेन्स के कैडेडस एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों, स्वच्छ भारत मिशन के लोगों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जनपद में वैक्टर जनित रोगों विशेषकर डेंगू की रोकथाम हेतु सजग रहने की सलाह दी एवं अपनी विभागीय गतिविधि को निरन्तर रखने हेतु निर्देशित किया।

प्रतिभागियों में मुख्य रूप में डा० आर०के० गुप्ता जिला सर्विलान्स अधिकारी, जी०के० मिश्रा जिला मलेरिया अधिकारी, डा. शिवी अग्रवाल एपिडिमियोलोजिस्ट, नरेन्द्र कुमार सहायक मलेरिया अधिकारी के साथ-साथ डब्लू०एच०ओ०, यूनीसेफ के जनपद शतरीय कोओर्डिनेटर, एन०सी०डी० विंग, नमिता सक्सेना मलेरिया निरीक्षक, मलेरिया विभाग के समश्त कार्मिक एवं आई०डी०एस०पी० यूनिट के समश्त कार्मिक द्वारा प्रतिभाग किया गया।

जिला संयुक्त चिकित्सालय के मुख्य अधीक्षक डा० संजय गुप्ता एवं समश्त चिकित्सक एवं पैरा मैडिकल स्टाफ द्वारा प्रतिभाग किया गया।

कार्यकम समाप्ति के उपरान्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजियाबाद द्वारा प्रतिभागी विद्यालयों को मूमेन्टों देकर सम्मानित किया एवं संचारी रोग नियंत्रण अभियान को सफल बनाने हेतु सहयोग की अपेक्षा की।

"शक्ति दीदी" के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को किया गया जागरूक

✷ **एनसीआर टुडे. अलीगढ़** ✷

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में जनपद में गठित मिशन शक्ति टीमों के द्वारा महिलाओं व बालिकाओं के सुरक्षार्थ चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान-5 के अंतर्गत समस्त थाना क्षेत्रों में कम्युनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु "शक्ति दीदी" के माध्यम से महिला सम्मान, सुरक्षा व जागरूकता हेतु अभियान चलाया जा रहा है।

मिशन शक्ति फेज-05 के विशेष अभियान (शक्ति दीदी) के तहत थानों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों, समस्त थानों पर गठित महिला सुरक्षा विशेष दल द्वारा गाँवों, कस्बों व मोहल्लों में जन चौपाल लगाकर तथा बस स्टैंड, बाजार, गांव, कस्बा, स्कूल, कॉलेज व कोचिंग सेंटर इत्यादि सार्वजनिक एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर बालिकाओं व महिलाओं से वार्ता कर महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के बारे में जागरूक करते हुए शक्ति दीदी के रुप में महिलाओं व बालिकाओं से जुड़ कर उन्हे सक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। शक्ति दीदी अभियान के तहत महिलाओं व बालिकाओं को शासन व यूपी पुलिस द्वारा चलाई जा रही सुरक्षा संबंधित सेवाएं जैसे वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, साइबर सम्बन्धी एवं सीयूजी नम्बरों के बारे में विश्तृत जानकारी देकर जागरुक किया जा रहा है। महिलाओ एवं बालिकाओं से वार्ता कर उनके अन्दर आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

चेयरपर्सन पुत्र शेख शहराज़ ख़लील ने नहर पर बन रही सड़क का निरीक्षण किया

✷ **एनसीआर टुडे. नगीना** ✷

नगर पालिका परिषद नगीना की चेयरपर्सन पुत्र शेख शहराज़ ख़लील ने नगीना मे मोहल्ला लुहारी सराय एसडीएम कोर्ट वाली नहर पर बन रही सड़क का निरीक्षण करते हुए उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता का जायजा भी लिया।

शेख शहराज़ ख़लील ने सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार से कहा कि सड़क निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान सभासद सिद्दीकी मुल्तानी, पूर्व सभासद मोहम्मद अफजाल, हाफिज जाकिर, आदि लोग मौजूद रहे। बताते चलें कि नगर पालिका परिषद नगीना की चेयरपर्सन नगर के चौमुखी विकास के लिए दिन-रात एक किए हैं। वही चेयर पर्सन पुत्र अपने मरहूम वालिद शेख खलील उर रहमान के सपनों को साकार करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। उन्होंने कहा कि नगर तथा क्षेत्र की जनता उनका परिवार है।

जन-आन्दोलन का रूप देने के लिए व्यापक रणनीति तैयार : डीएम

✷ **एनसीआर टुडे. अलीगढ़** ✷

जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में जिला पर्यावरण एवं वृक्षारोपण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में वृक्षारोपण अभियान-2025 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न बिन्दुओं पर विश्तार से चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि "पेड़ लगाओ-पेड़ बचाओ" को जन-आन्दोलन का स्वरूप देने के लिए सभी विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं आमजन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशानुसार प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों एवं जीरो पॉवर्टी कार्यक्रम में चयनित परिवारों द्वारा दो-दो सहजन के पौधे लगवाना अनिवार्य किया गया है। सहजन के औषधीय एवं पौष्टिक गुणों के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि गंगा बेसिन क्षेत्र सहजन वृक्ष के लिए उपयुक्त है और इसे खेतों की मेड़, घरों के आंगन, स्कूलों एवं पार्कों में आसानी से लगाया जा सकता है।

बैठक में वृक्षारोपण में जनसहभागिता बढ़ाने के लिए रोटरी क्लब, लाइंस क्लब, हमसफर एजुकेशनल सोसाइटी, एनसीसी, एनएसएस, लोक भारती और व्यापार मंडल जैसी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए। इनके लिए प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग नवीन प्रकाश, जिला विद्यालय निरीक्षक पूरन सिंह एवं जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

वर्षाकाल वृक्षारोपण के लिए पौध रोपण स्थलों पर स्मार्टफोन से भू-निर्देशांक सहित फोटोग्राफी एवं हरीतिमा ऐप के माध्यम से जियो टैगिंग सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत शतर पर ग्रामीण रोजगार सेवकों को इसके लिए नामित किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने शौर्य वन, गोपाल वन एवं ऑक्सी वन की स्थापना के लिए विभागवार कार्ययोजना बनाने के निर्देश देते हुए कहा की शौर्य वन स्वतंत्रता दिवस को शहीद सैनानियों के गांवों में उनकी स्मृति में स्थापित किया जाएगा। गोपाल वन गौशालाओं में छायादार एवं चारा प्रजातियों के पौधों के रोपण के लिए स्थानीय गोपालकों व संत समाज की भागीदारी से स्थापित होगा। ऑक्सी वन नगर निगम क्षेत्रों में वायु प्रदूषण नियंत्रण और जैवविविधता संरक्षण के लिए स्कूली बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सहभागिता से विकसित किए जाएंगे।

वन विभाग द्वारा पौधशालाओं से निशुल्क पौध वितरण के लिए क्पतमबज ँचसपदह ज्तंदेमित ँ वजिूतम के माध्यम से फत ब्वकमक प्दकमदज जारी किये जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने सभी विभागों से आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष पौध उठान शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

इसके अतिरिक्त, अतिविशिष्ट व्यक्तियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने, कार्यक्रमों का समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराने तथा वृक्षारोपण स्थलों की सुरक्षा के लिए बाउंड्रीवाल या जैविक तारबाड़ की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी नवीन प्रकाश, अग्निशमन अधिकारी अरविंद कुमार सिंह, सहजिला विद्यालय निरीक्षक राजकिशोर, सहायक नगर आयुक्त राकेश यादव, सीवीओ डॉ दिवाकर त्रिपाठी, डीसी मनरेगा अनुज सक्सेना, जिला विकास अधिकारी आलोक आर्या, एआरटीओ प्रवेश कुमार, सहायक महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र ब्रजेश यादव, डीपीआरओ यतेंद्र सिंह सहित सभी सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

नगीना सांसद चंद्रशेखर को मिली जान से मारने की धमकी

पार्टी कार्यकर्ताओं ने नगीना में कराया मुकदमा दर्ज

✷ **एनसीआर टुडे. नगीना** ✷

आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना लोकसभा क्षेत्र के सांसद चंद्रशेखर को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दस दिन में जान से मारने की धमकी दी है।

पार्टी के हेल्पलाइन नंबर के व्हाट्सएप पर दस दिन में मारने की धमकी देने का मामला सोशल मीडिया के जरिए सामने आया है। सोशल मीडिया पर पार्टी द्वारा खुद इस बात की जानकारी साझा की गई है। आजाद समाज पार्टी नगीना कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी को प्रार्थना देकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले का नंबर भी जारी किया है। इस बारे में सांसद चंद्रशेखर का कहना है कि उनकी पार्टी ने धमकी देने वाले के नंबर व उसके द्वारा भेजे गए मैसेज की जानकारी पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी दे दी है।

उनका कहना है कि अब पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे इस मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार करे। इस मौके पर आजाद समाज पार्टी नगीना कार्यकारिणी के कार्यकर्ता असलम सिद्दीकी अहमद अंसारी जावेद अहमद अरविंद कुमार नरेंद्र कुमार ज्ञान सिंह जी परवेज पासी आदि उपस्थित रहे ।

ई-रिक्शा बना मौत की सवारी ठूंस-ठूंसकर भरी जाती है सवारी, प्रशासन को हादसे का इंतजार

✷ **एनसीआर टुडे. अफजलगढ़** ✷

नगर में ई-रिक्शा चालकों की बेलगाम लापरवाही अब जानलेवा रूप लेती जा रही है। ये चालक अपनी कमाई के लालच में छोटे-छोटे बच्चों की जान से खिलवाड़ करने से भी नहीं चूक रहे। बेकाबू भीड़, ओवरलोडिंग और सुरक्षा की पूरी अनदेखी ये ई-रिक्शा अब किसी चलते-फिरते खतरे से कम नहीं हैं। शनिवार को बस अड्डे के पास एक ई-रिक्शा में जो दृश्य नजर आया, वह हैरान कर देने वाला था।

मासूम बच्चे ई-रिक्शा के पीछे खड़े थे, वहीं पीछे से रोडवेज बस आ रही थी। ज़रा सी चूक होती तो बड़ा हादसा तय था। यह कोई एक दिन का मामला नहीं, बल्कि आए दिन ई-रिक्शा चालक इसी तरह ठूंस-ठूंस कर सवारियां भरते हैं।

नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न कोई रोक-टोक, न किसी तरह की कार्यवाही। बच्चों को इस तरह लटकाकर ले जाना किसी अपराध से कम नहीं स्थानीय नागरिकों ने गहरी नाराज़गी जताते हुए कहा कि अगर कोई हादसा होता है तो क्या प्रशासन जिम्मेदारी लेगा क्या ई-रिक्शा चलाने वालों पर कोई निगरानी नहीं है क्या किसी की जान जाने का इंतजार है।

परिवहन विभाग और प्रशासन को अब नींद से जागना होगा। ओवरलोडिंग, खासकर बच्चों के मामले में, सख्त कार्यवाही जरूरी है।

अन्यथा, यह लापरवाही किसी दिन किसी मासूम की जान ले सकती है, और तब जागने का कोई फायदा नहीं होगा।

युवजन सभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य

अदनान ने समर्थकों के साथ मनाया अखिलेश यादव का जनमदिवस

✷ **एनसीआर टुडे. शेरकोट** ✷

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 52वां जन्मदिन मोहल्ला शेखान मे युवजन सभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अदनान राईन व नगर अध्यक्ष बरकत अब्बासी ने अपने कार्यालय पर धूमधाम से मनाया गया।

इस अवसर पर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने केक काटा, और एक-दूसरे को खिलाकर तथा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की लंबी उम्र व अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए युवजन सभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अदनान राईन ने कहा कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नई सोच और सकारात्मक दिशा दी है।

उनके कार्यकाल में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ, युवाओं को प्रेरणा और किसानों को राहत मिली।

पीडीए को एकजुट कर उन्होंने भाजपा सरकार को बैसाखी पर ला दिया है।

जन्मदिन के उपलक्ष्य में आगामी 2027 के चुनाव में सपा की सरकार बनवाने का संकल्प के साथ साथ ही सपा नगर अध्यक्ष बरकत अब्बासी ने कार्यकर्ताओं के साथ पौधा रोपण किया। समाज को हरियाली और स्वच्छता का संदेश दिया।

इस दौरान बरकत अब्बासी ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा हम सभी का सामूहिक दायित्व है।

पौधारोपण करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। इस मौके पर अजमतुल्ला अब्बासी, कृपाल सिंह सैनी,वसीम अब्बासी, बब्बन राईन, शेख शुऐब, जिया अहमद सेट्टू, तसलीम घोसी, भोला कुरैशी, शेख मुश्तकिम, शेख नईम, मास्टर राजेश आदि सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे।

चोरी की ई-रिक्शा सहित दो अभियुक्त गिरफ्तार

✷ **एनसीआर टुडे. अलीगढ़** ✷

1 जूलाई 2025 को जीमल पुत्र वसीम निवासी मजीपुर सुवकरा थाना गोण्डा जिला अलीगढ़ ने थाने आकर सूचना दी कि मैं अपनी ई-रिक्शा किराये पर सामान ढोने में चलाता हूँ।

दो व्यक्ति मुझे मेरी टिर्री सहित अपना सामान लेने के लिये लेकर गये, राश्ते में उन्होने टिर्री रुकवाकर कहा कि सामान थोड़ी दूर रखा है आप देख आओ, सामान देखने चला गया, वापस आया तो ई-रिक्शा नहीं मिला इस संबंध में थाने में बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सासनीगेट पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से अभियुक्तगण मनोज पुत्र प्रेमसिंह निवासी सराय वृन्दावन बन्टी के मकान में किराये पर थाना सासनी गेट जनपद अलीगढ़ स्थाई पता तैयबपुर कमालपुर थाना ढोलना जिला कासगंज व राहुल कुमार पुत्र कमल सिंह हाल निवासी सराय वृन्दावन बन्टी के मकान मे किराये पर थाना सासनी गेट जनपद अलीगढ़ व स्थाई पता सूरतगढ़ थाना अतरौली जपनद अलीगढ़ को चोरी की गई ई-रिक्शा सहित गिरफ्तार किया।

दुकान में लगी आ, हैंडलूम का सामान जलकर राख

✷ **एनसीआर टुडे. अलीगढ़** ✷

थाना गांधीपार्क इलाके के जीटी रोड़ पर सोमवार देर रात्रि एक दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।

आग लगने की सूचना पर इलाका पुलिस के अलावा दमकल टीम मौके पर आ गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक लाखों रुपए का माल आग में जलकर राख हो चुका था। घटना से इलाके में काफी देर तक खलबली का माहौल बना रहा।

बी दास कंपाउंड में रहने वाले आदेश महाजन कपड़े का कारोबार करते हैं। छर्रा अड्डा रेलवे पुल के पास महाजन फोम के नाम से उनकी दुकान है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन की तरह सोमवार की शाम दुकान बंद कर वह घर चले गए।

इसके बाद देर रात अचानक दुकान में आग लग गई। दुकान से धुआं निकलता देख आस पास रहने वाले लोगों को अनहोनी घटना होने का शक हुआ। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया।

भीषण आग का नजारा देख लोगों में खलबली मच गई। लोगों ने घटना की खबर कंट्रोल रूम को दी। इलाका पुलिस के अलावा दमकल की तीन गाड़ियां मोके पर पहुंच गई।

दमकल अधिकारी ने बताया शार्ट सर्किट से आग लगना प्रतीत हो रहा है। करीब आधे घण्टे में आ पर काबू पा लिया गया।

दुकान मालिक ने बताया कि आग से कम से कम 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दुकान के अंदर गद्दा, कुर्सी, कंबल आदि (हैंडलूम का पूरा सामान) रखा था। जोकि आग में जलकर राख हो गया। दुकान बंद करते समय लाइट ऑफ कर की थी। फिर भी आग कैसे लगी पता नहीं।

स्टंट करना पड़ा महंगा, गाड़ी सीज, चालान, तीन आरोपी गिरफ्तार

✷ **एनसीआर टुडे. ग्रेटर नोएडा** ✷

ग्रेटर नोएडा में कुछ युवाओं को कार से स्टंटबाजी इतनी महंगी पड़ी की लाखों रुपए का चालान भी हुआ, गाड़ियां सीज हुई और उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी।

रील बनाने के चक्कर में यह युवा लगातार अपने और दूसरे की जान को खतरे में डालकर स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और इनका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी कड़ा कदम उठाती है।

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वायरल हुए स्टंटबाजी के एक वीडियो में कुछ युवक कारों से लटकते हुए बीच सड़क पर खतरनाक स्टंट

करते नजर आ रहे थे। इस वीडियो को जैसे ही ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने संज्ञान में लिया, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई शुरू की गई। वीडियो की जांच के बाद थाना नॉलेज पार्क में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान उदय प्रताप सिंह, निवासी सोंगरा, थाना अकराबाद, जिला अलीगढ़ (वर्तमान पता – प्रताप विहार, गाजियाबाद), शिवम पटेल, निवासी अल्फा-1, थाना बीटा-2 और प्रिंस भारद्वाज, निवासी बनवारीवास, थाना जेवर के रूप में हुई है।

इन युवकों ने ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर सार्वजनिक यातायात को खतरे में डालते हुए नियमों की धज्जियां उड़ाई थीं। वीडियो में जिन कारों से स्टंट किए जा रहे थे, उनकी पहचान कर ली गई है। पुलिस ने तीनों कारों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत सीज कर दिया है।

वीडियो सामने आने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए दो गाड़ियों पर भारी चालान लगाया। एक गाड़ी पर 63,500 रुपए और दूसरी पर 57,500 रुपए का चालान काटा गया है।

संपादकीय

मध्यम वर्गीय परिवार नहीं फंसे ऋण के जाल में

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 50 आधार बिंदुओं की कमी की है। इसके साथ ही, निजी क्षेत्र के बैंकों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं क्रेडिट कार्ड कम्पनियों सहित अन्य वित्तीय संस्थानों ने भी अपने ग्राहकों को प्रदान की जा रही ऋणराशि पर लागू ब्याज दरों में कमी की घोषणा करना प्रारम्भ कर दिया है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में की गई कमी का लाभ शीघ्र ही भारत में ऋणदाताओं तक पहुंच सके एवं इससे अंततः देश की अर्थव्यवस्था को बल मिल सके। भारत में चूंकि अब मुद्रा स्फीति की दर नियंत्रण में आ गई है।

अतः आगे आने वाले समय में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में और अधिक कमी की जा सकती है। इस प्रकार, बहुत सम्भव है ऋणराशि पर लागू ब्याज दरों में कमी के बाद कई नागरिक जिन्होंने पूर्व में कभी बैंकों से ऋण नहीं लिया है, वे भी ऋण लेने का प्रयास करें। बैंक से ऋण लेने से पूर्व इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि इस ऋण को चुकाता करने की क्षमता भी ऋणदाता में होनी चाहिए अर्थात ऋणदाता की पर्याप्त मासिक आय होनी चाहिए ताकि बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण की किश्त एवं ब्याज का भुगतान पूर्व निर्धारित समय सीमा के अंदर किया जा सके। इस संदर्भ में विशेष रूप से युवा ऋणदाताओं द्वारा क्रेडिट कार्ड के उपयोग पश्चात संबंधित राशि का भुगतान समय सीमा के अंदर अवश्य करना चाहिए क्योंकि अन्यथा क्रेडिट कार्ड एजेंसी द्वारा चूक की गई राशि पर भारी भरकम ब्याज की दर से दंड वसूला जाता है, जिससे युवा ऋणदाता ऋण के जाल में फंस जाते हैं। बैंकों से लिए गए ऋण की मासिक किश्त एवं इस ऋणराशि पर ब्याज का भुगतान यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं किया जाता है तो चूककर्ता ऋणदाता से बैंकों द्वारा दंडात्मक ब्याज की वसूली की जाती है।

इसी प्रकार, कई नागरिक जो क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं एवं इस क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध उपयोग की गई राशि का भुगतान यदि वे निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं कर पाते हैं तो इस राशि पर चूक किए गए क्रेडिट कार्ड धारकों से भारी भरकम ब्याज की दर से दंड वसूला जाता है। कभी कभी तो दंड की यह दर 18 प्रतिशत से 24 प्रतिशत के बीच रहती है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले नागरिक कई बार इस उच्च ब्याज दर पर वसूली जाने वाली दंड की राशि से अनभिज्ञ रहते हैं। अतः बैंकों से ली जाने वाली ऋणराशि एवं क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली राशि का समय पर भुगतान करने के प्रति ऋणदाताओं को सजग रहने की आवश्यकता है।

कुल मिलाकर यह ऋणदाताओं के हित में है कि वे बैंक से लिए जाने वाले ऋण की राशि तथा ब्याज की राशि एवं क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली राशि का पूर्व निर्धारित एवं उचित समय सीमा के अंदर भुगतान करें क्योंकि अन्यथा की स्थिति में उस चूककर्ता नागरिक के क्रेडिट रेटिंग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है एवं आगे आने वाले समय में उसे किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है एवं बहुत सम्भव है कि भविष्य में उसे किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त ही न हो सके।

ऋणदाता यदि किसी प्रामाणिक कारणवश अपनी किश्त एवं ब्याज का बैंकों अथवा क्रेडिट कार्ड कम्पनी को समय पर भुगतान नहीं कर पाता है और उसका ऋण खाता यदि गैर निष्पादनकारी आशित में परिवर्तित हो जाता है तो इस संदर्भ में चूककर्ता ऋणदाता द्वारा बैंकों को समझौता प्रश्ताव दिए जाने का प्रावधान भी है। इस समझौता प्रश्ताव के माध्यम से चूककर्ता ऋणदाता द्वारा सम्बंधित बैंक अथवा क्रेडिट कार्ड कम्पनी को मासिक किश्त एवं ब्याज की राशि को पुनर्निर्धारित किए जाने के सम्बंध में निवेदन किया जा सकता है। परंतु, यदि ऋणदाता ऋण की पूरी राशि, ब्याज सहित, अदा करने में सक्षम नहीं है तो चूक की गई राशि में से कुछ राशि की छूट प्राप्त करने एवं शेष राशि को एकमुश्त अथवा किश्तों में अदा करने के सम्बंध में भी समझौता प्रश्ताव दे सकता है। ऋण की राशि अथवा ब्याज की राशि के सम्बंध के प्राप्त की गई छूट की राशि का रिकार्ड बनता है एवं समझौता प्रश्ताव के अंतर्गत प्राप्त छूट के चलते भविष्य में उस ऋणदाता को बैकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान चूककर्ता ऋणदाता को रखना चाहिए। अतः जहां तक सम्भव को ऋणदाता द्वारा समझौता प्रश्ताव से भी बचा जाना चाहिए एवं अपनी ऋण की निर्धारित किश्तों एवं ब्याज का निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत भुगतान करना ही सबसे अच्छा राश्ता अथवा विकल्प है।

भारत में तेज गति से हो रही आर्थिक प्रगति के चलते मध्यमवर्गीय नागरिकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, जिनके द्वारा चार पहिया वाहनों, स्कूटर, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन एवं मकान आदि आशितयों को खरीदने हेतु बैंकों अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया जा रहा है। कई बार मध्यमवर्गीय परिवार एक दूसरे की देखा देखी आपस में होड़ करते हुए भी कई उत्पादों को खरीदने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे उस उत्पाद विशेष की आवश्यकता हो अथवा नहीं। उदाहरण के लिए एक पड़ौसी ने यदि अपने चार पहिया वाहन का एकदम नया मॉडल खरीदा है तो जिस पड़ौसी के पास पूर्व में ही चार पहिया वाहन उपलब्ध है वह पुराने मॉडल के वाहन को बेचकर पड़ौसी द्वारा खरीदे गए नए मॉडल के चार पहिया वाहन को खरीदने का प्रयास करता है और बैंक के ऋण के जाल में फंस जाता है। यह नव धनाडय वर्ग यदि बैक से लिए गए ऋण की किश्त एवं ब्याज की राशि का निर्धारित समय सीमा के अंदर भुगतान नहीं कर पाता है तो उस नागरिक विशेष के वित्तीय रिकार्ड पर धब्बा लग सकता है जिससे उसके लिए उसके शेष जीवन में बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से पुनः ऋण लेने में कठिनाई आ सकती है।

अतः बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले नागरिकों को ऋण की किश्त का समय पर भुगतना करना स्वयं उनके हित में हैं, ताकि भारत में तेज हो रही आर्थिक प्रगति का लाभ आगे आने वाले समय में भी समश्त नागरिक ले सकें। भारत में तो यह कहा भी जाता है कि जिसके पास जितनी चादर हो, उतने ही पैर पसारने चाहिए। अर्थात, नागरिकों को बैंकों से ऋण लेते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऋण की किश्त एवं ब्याज की राशि का भुगतान करने लायक उनकी अतिरिक्त आय होनी चाहिए, ताकि ऋण की किश्तों एवं ब्याज की राशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के अंदर किया जा सके एवं उनका ऋण खाता गैर निष्पादनकारी आशित में परिवर्तित नहीं हो।

किसान-खाद्य सुरक्षा के विरुद्ध हैं ये सिफारिशें

डा. अश्विनी महाजन

कुछ दिन पहले नीति आयोग के एक वर्किंग पेपर में भारत सरकार को सिफारिश की है कि वर्तमान में प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में जैव परिवर्द्धित (जीएम) कृषि उत्पादों के आयात को अनुमति दे दी जाए। इसमें नीति आयोग ने मक्का, सोयाबीन जैसी फसलों का उदाहरण भी दिया है, जिनके आयात को खोल दिया जाना चाहिए।

वर्किंग पेपर में यह भी राय दी गई है कि सरकार इस समझौते में उन कृषि उत्पादों के आयात को भी खोलने का प्रस्ताव करे जिन्हें भारत में या तो पैदा नहीं किया जाता है या उनका उत्पादन इतना कम है कि उनके आयात से किसानों पर खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस संबंध में वर्किंग पेपर में चावल, काली मिर्च, सोयाबीन तेल, झींगा, चाय, कॉफी, डेयरी उत्पादन, पोल्ट्री, सेब, बादाम, पिश्ता आदि का उदाहरण दिया गया है, जिनके आयात को नीति आयोग ने खोलने की सिफारिश की है।

इस वर्किंग पेपर की सिफारिशों के बाद भारतीय किसान संघ सहित किसान संगठनों की कड़ी प्रतिक्रिया आई है और इस संबंध में नीति आयोग की पुरजोर निंदा भी की गई है और यह कहा गया है कि ये सुझाव किसानों के हितों के प्रतिकूल हैं। उदाहरण के लिए भारतीय किसान संघ ने कहा है कि ये सुझाव देश और किसान हितों के खिलाफ हैं। किसान संघ का यह भी कहना है कि नीति आयोग का अमेरिका के सामने घुटने टेकना अच्छा संकेत नहीं है।

लेकिन दूसरी ओर यह भी खबर है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताओं में अवरोध आ गया है क्योंकि सरकार अमेरिका की इस मांग कि भारत, अमेरिका के जीएम कृषि उत्पादों और अन्य कृषि उत्पादों के लिए बाजार खोले, को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में नीति आयोग का यह वर्किंग पेपर नीति आयोग की सरकार की स्थिति को समझ नहीं पा रहा है। इसका यह भी मतलब हो सकता है कि नीति आयोग सरकार की जीएम विरोधी स्थिति को बदलने हेतु प्रयास कर रहा है।

यह दोनों ही स्थितियां देश के लिए शुभ नहीं हैं। पहले भी नीति आयोग ने की थी जीएम की पैरवी : यह पहला अवसर नहीं है कि जब नीति आयोग ने जीएम फसलों की पैरवी की है। इससे पहले प्रो. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में भी नीति आयोग ने जीएम फसलों के पक्ष में रिपोर्ट जारी की थी। उस समय भी इसका पुरजोर विरोध हुआ था।

क्यों सही नहीं है नीति आयोग की जीएम पैरवी : देश में लंबे समय से जीएम फसलों का विरोध चल रहा है। जीएम के पक्षधरों द्वारा लगातार जीएम के पक्ष में प्रयास किए जाते रहे हैं। लेकिन जीएम के पुरजोर विरोध और ठोस तर्कों के चलते, जीएम समर्थकों को सफलता हाथ नहीं लगी। इनके विरोध के कई कारण हैं- पहला कारण तो यह है कि अधिकांश जीएम फसलें शाकनाशक रोधी यानी हर्बिसाइड टोलरेंट हैं। यानी जब ये फसलें उगाई जाती हैं, तो उसके आसपास के जितने भी शाक हैं, वे सभी शाकनाशकों द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं और जीएम फसलों पर असर नहीं पड़ता।

लेकिन ऐसे वैज्ञानिक तथ्य मौजूद हैं जो यह साबित करते हैं कि यह शाकनाशक, कैंसरकारी यानी 'कोर्सीनोजेनिक' है। गौरतलब है कि जब इन शाकनाशकों का उपयोग जीएम फसलों के उत्पादन के दौरान किया जाता है तो उसके कुछ अवशेष अवश्य उन कृषि उत्पादों में रह जाते हैं, जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में प्रति लाख जनसंख्या पर 350 कैंसर के मरीज हैं, जबकि भारत में यह आंकड़ा 100 प्रति लाख का है।

इसका एक कारण जीएम फसलों में इश्तेमाल किए जाने वाले शाकनाशकों का अधिक उपयोग भी है। हालांकि भारत में खाद उत्पादों में जीएम बीजों का उपयोग और आयात वर्जित है, लेकिन कुछ समय से खाद्य तेलों की कमी के चलते अमेरिका और अन्य देशों से खाद्य तेलों का आयात बढ़ रहा है, जिनमें से

कुछ मात्रा में जीएम खाद्य तेलों का भी आयात अनजाने में हो रहा है। यह बात भारत सरकार ने पहले भी स्वीकार की है। इसके कारण भारत में कैंसर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। 2000 में जहां मात्र 8 लाख कैंसर मरीज थे, वर्ष 2024 तक उनकी संख्या 15 लाख तक पहुंच चुकी है। जीएम खाद्य तेलों का सेवन भी एक कारण हो सकता है।

जीएम फसलों के आयात के विरोध का दूसरा कारण यह है कि वर्तमान में भारत के नियमों के अनुसार देश में जीएम फसलों के उत्पादन और आयात की अनुमति नहीं है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में व्यापारिक साझेदार देशों द्वारा अन्य साझेदार देश के नियमों का आदर करते हुए इस बाबत कोई विवाद नहीं खड़ा किया जा सकता। डब्ल्यूटीओ नियमों के अधीन हर देश को यह अधिकार है कि वह अपने देशवासियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर अन्य देशों से आने वाले सामान पर रोक लगा सके।

अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार चूंकि ऐसा संभव है कि अमरीका से आने वाले जीएम उत्पादों को देश में आने से रोका जा सके। चूंकि भारत के किसान पहले से ही अपनी उपज के सही मूल्य न पाने के कारण आर्थिक रूप से नुकसान उठा रहे हैं, यदि अमरीका से आने वाले सश्ते जीएम उत्पादों को आने की अनुमति दे दी जाती है तो हमारे किसानों को और अधिक नुकसान होगा और ऐसे में किसान यदि कृषि से बाहर होते हैं तो देश की खाद्य सुरक्षा ही खतरे में पड़ सकती है।

तीसरे, भारत के फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) द्वारा बनाए गए खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत जीएम उत्पादों की बिक्री संभव नहीं है। ऐसे में देश में जीएम उत्पादों के आयात के बाद वे भारत की खाद्य श्रृंखला में शामिल हो जाएंगे, जिससे देश के नियमों का तो उल्लंघन होगा ही, देशवासियों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडराने लगेगा।

उपरोक्त कारणों के अलावा एक चौथा कारण, जो देश में जीएम उत्पादों के आयात के विरोध में जाता है, वो यह है कि जिन जीएम उत्पादों के आयात को खोलने हेतु नीति आयोग ने सिफारिश की है, वो अमरीका में वाश्तव में मनुष्य द्वारा उपभोग नहीं किए जाते। अमरीका में मक्का और सोया का उपयोग अधिकांशतः या तो जानवरों के चारे के रूप में किया जाता है या एथनॉल बनाने में। गौरतलब है कि अमरीका में जीएम मक्का का 40 से 50 प्रतिशत इश्तेमाल जानवरों के चारे के रूप में, 30 से 40 प्रतिशत इश्तेमाल एथनॉल बनाने में और मात्र 10 प्रतिशत खाद्य प्रसंस्करण में इश्तेमाल किया जाता है।

इसी प्रकार सोया का भी इश्तेमाल अधिकांशतः पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। ऐसे में जीएम उत्पादों का भारत की खाद्य श्रृंखला में शामिल होना देशवासियों के स्वास्थ्य के लिए ही हानिकारक नहीं है, बल्कि यह देशवासियों का अपमान भी है। वैसे तो नीति आयोग में बैठे लोगों द्वारा जीएम उत्पादों की लगातार वकालत की ही जाती है, लेकिन देश में किसानों और प्रबुद्ध वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे विरोध के कारण और न्यायालयों द्वारा इस बाबत अनुमति न मिलने के कारण वे सफल नहीं हो पा रहे हैं।

ऐसे में जब अमरीका के साथ व्यापार समझौते की बात चल रही है, और किसानों व डेयरी के हितों की रक्षा हेतु भारत में खाद्य जीएम पर प्रतिबंध एक ढाल की तरह इश्तेमाल किया जा सकता है, नीति आयोग द्वारा इस प्रकार की सिफारिशें उनकी किसानों के प्रति प्रतिबद्धता, देश के लोगों की स्वास्थ्य और देश की खाद्य सुरक्षा के प्रति उदासीनता की परिचायक हैं।

इसके अलावा, हमें यह भी समझना होगा कि भारत लगभग 50 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के कृषि खाद्य उत्पादों का निर्यात करता है, और भारतीय खाद्य पदार्थों का मुख्य आकर्षण यह है कि वे गैर-जीएम टैग वाले होते हैं। जैसे ही जीएम हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है, हम अपने निर्यात बाजारों का एक बड़ा हिस्सा खो सकते हैं, क्योंकि मध्य पूर्व के देश और यूरोपीय तथा कई अन्य देश जीएम खाद्य उत्पादों के आयात की अनुमति नहीं देते हैं। शायद, नीति आयोग द्वारा भारत में जीएम आयात और उत्पादन से जुड़े इस महत्वपूर्ण जोखिम को नहीं रखा गया है।

टीएमसी नेताओं की निर्लज्ज टिप्पणियों से उठा विवाद

ललित गर्ग

कोलकत्ता में कानून की एक छात्रा से सामूहिक दुराचार-गैंगरेप का मुद्दा एक बार फिर पश्चिम बंगाल में जितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने लगा है उतना ही बड़ा नारी उत्पीड़न का मुद्दा बनकर उभर रहा है। इस मामले में पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं की अनर्गल एवं निर्लज्ज टिप्पणी स्त्री की मर्यादा, सम्मान एवं अस्मिता के खिलाफ शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण व संवेदनहीन प्रतिक्रिया है। इन नेताओं ने गैंगरेप मामले पर विवादित बयान से राज्य एवं देश में भारी जनाक्रोश पैदा हो गया था।

विशेषतः राजनेताओं के बयानों एवं सोच में एक बार फिर शर्मनाक ढंग से पीड़िता पर दोष मढ़ने की बेशर्म कोशिश की गई है। इस मामले में सत्तारूढ़ टीएमसी पार्टी अन्दर एवं बाहर दोनों मोर्चों पर घिरती हुई नजर आ रही है। जहां इस मामले में पार्टी के अन्दर गुटबाजी एक बार फिर सामने आयी है, वहीं भाजपा आक्रामक रूप से ममता सरकार को घेर रही है। टीएमसी की महिला नेत्री महुआ मोइत्रा टीएमसी नेताओं कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा के उन बयानों पर निराशा व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया है कि इन राजनेताओं के बयान में स्त्री-द्वेष पार्टी लाइन से परे है।

यह एक बदतर स्थिति है कि जिस पार्टी के नेताओं ने ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिए हैं, उस पार्टी की सुप्रीमो एक महिला ही है। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि ममता बनर्जी जैसी तेजतर्रार मुख्यमंत्री के शासन और नेतृत्व के वर्षों के दौरान टीएमसी के भीतर नारी सम्मान एवं अस्मिता को लेकर संवेदनशीलता लाने और मानसिकता में बदलाव लाने के प्रयास विफल होते नजर आ रहे हैं। अकसर महिलाएं और महिला राजनेता पुरुष नेताओं के हाथों अश्लील, अभद्र और तौहीन भरी टिप्पणओं की शिकार होती रही हैं।

ऐसे बयानों के बावजूद अकसर ये राजनेता किसी कठोर कार्रवाई की बजाय हल्की फुल्की फ़टकार के बाद बच निकलते हैं। ये बयान कभी महिलाओं की बॉडी शेमिंग करते नज़र आते हैं तो कभी बलात्कार जैसे गंभीर अपराध को मामूली बताने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही ये चिन्ताजनक संदेश भी जाता है कि महिलाओं के बारे में हल्के और आपत्तिजनक बयान देना विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के लिये सामान्य बात है।

जब किसी देश की बेटियां न्याय का अध्ययन कर रही हों और वहीं उनके साथ अन्याय की पराकाष्ठा हो तो यह केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि पूरे समाज, व्यवस्था और सोच के लिए एक जघन्य आइना बन जाती है। प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार की घटना ने न केवल राजनीतिक सोच एवं कानून के मंदिरों को शर्मसार किया है, बल्कि हर संवेदनशील मन को झकझोर दिया है।

पीड़िता एक लॉ कॉलेज में अध्ययनरत छात्रा थी, जो अपने उज्ज्वल भविष्य के सपनों के साथ शिक्षा के पथ पर अग्रसर थी। घटना की रात वह अपने कुछ परिचितों के साथ बाहर थी, जिनमें से ही कुछ ने उसकी अस्मिता को रौंद डाला। उसे नशा दिया गया और फिर सुनसान स्थान पर ले जाकर कई लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया।

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है, लेकिन सवाल यह है कि जब कानून पढ़ने वाली लड़की खुद असुरक्षित है, तो आम महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी? क्या यह कानून की शिक्षा देने वाली संस्थाओं एवं शासन करने वाली सत्ताओं के लिए आत्ममंथन का समय नहीं है? ऐसी घटनाओं पर निर्भया कांड के बाद बने कानूनों का सख्ती से पालन हो।

रेप को सिर्फ एक 'जुर्म' नहीं, 'राष्ट्रीय आपदा' माना जाए, और उसकी रोकथाम के लिए शिक्षा, संस्कार और तकनीकी सुरक्षा साधनों को प्राथमिकता दी जाए। कोलकाता की लॉ छात्रा की यह दर्दनाक घटना हमें चेताती है कि केवल कानून बना लेना काफी नहीं, जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक बेटियां असुरक्षित रहेंगी।

यह केवल एक छात्रा की लड़ाई नहीं, बल्कि हर बेटी की सुरक्षा की लड़ाई है। न्याय तब होगा जब ऐसी घटनाएं रुकेंगी और उसके लिए हमें मिलकर लड़ना होगा।

सबसे दुखद पहलू यह है कि अनेक बार ऐसी घटनाओं में समाज चुप रहता है, पीड़िता को दोषी ठहराने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया पर तंज, मीडिया ट्रायल और व्यक्तिगत चरित्रहनन जैसी बातें पीड़िता को न्याय से अधिक पीड़ा देती हैं।

पीड़िता के लिये यह पीड़ा तब और बढ़ जाती है जब उनके जन-प्रतिनिधि निर्लज्ज बयानबाजी करते हैं। विडंबना यह है कि पीड़िता के प्रति निर्लज्ज बयानबाजी अकेले पश्चिम बंगाल का ही मामला नहीं है, देश के अन्य राज्यों में भी ऐसी संवेदनहीन टिप्पणियां सामने आती रही हैं। यदि इक्कीसवीं सदी के खुले समाज में हम महिलाओं के प्रति संकीर्णता की दृष्टि से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो इसे विडंबना ही कहा जाएगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही कि ये वे लोग हैं जिन्हें जनता अपना नेता मानती है और लाखों लोग उन्हें चुनकर जनप्रतिनिधि संस्थाओं में कानून बनाने व व्यवस्था चलाने भेजते हैं।

देश में बढ़ रही यौन-शोषण, रेप एवं नारी दुराचार की घटनाओं को देखते हुए जन-प्रतिनिधियों को ज्यादा संवेदनशील होने की अपेक्षा की जाती है। बड़ा प्रश्न है कि आखिर किसी राजनेता को हर महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार और यौन शोषण को असंवेदनशील तरीके से देखने की छूट क्यों एवं कैसे मिल जाती है।

भारत ही ऐसा देश है, जहां महिलाओं की अस्मिता एवं अशितत्व को तार-तार करने वाले नेताओं के निर्लज्ज बयानों के बावजूद उन पर कोई ठोस, सख्त एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होती। जबकि विश्व के अन्य देशों में ऐसा नहीं है। जैसे 2017 में ब्रिटेन के एक पार्षद के सामान्य से बयान पर अच्छा खासा बवाल मचा था। पार्षद ने सांसद का चुनाव लड़ रही एक गर्भवती महिला राजनेता के बारे में कह दिया था, 'वो गर्भवती हैं और उनका समय तो नैपी बदलने में ही बीत जाएगा, वो आम लोगों की आवाज़ क्या उठाएंगी?' इसके लिए पार्षद को माफ़ी मांगनी पड़ी।

ब्रिटेन जैसे कई देशों में अकसर ऐसे बयानों पर कार्रवाई होती है। मिसाल के तौर पर 2017 में ही यूरोपियन संसद के एक सांसद ने बयान दिया था कि महिलाओं को कम पैसा मिलना चाहिए क्योंकि वो कमज़ोर, छोटी और कम बुद्धिमान होती हैं। ' इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था और उन्हें मिलने वाला भत्ता भी बंद हो गया था।

कोलकाता की लॉ छात्रा मामले में टीएमसी नेताओं की टिप्पणियां निस्संदेह निंदनीय हैं, लेकिन पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की जानी चाहिए। ममता बनर्जी के सामने एक और चुनौती है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार-हत्याकांड और उसके बाद देश भर में उपजा आक्रोश अभी भी यादों में ताजा है।

निस्संदेह, केवल टिप्पणियों से पार्टी को अलग कर देना ही पर्याप्त नहीं है। सार्वजनिक जीवन में नारी सम्मान एवं जीवन-मूल्यों के खिलाफ जाने वाले लोगों के लिये परिणाम तय होने चाहिए। अन्यथा समाज में ये संदेश जाएगा कि ऐसे कुत्सित प्रयासों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है।

किसी अपराध की रोकथाम अच्छे शासन की अनिवार्य शर्त बनना चाहिए लेकिन जब कोई अपराध होता है तो प्रभावी प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। टीएमसी दोनों ही मामलों में विफल प्रतीत होती है। ऐसे मामलों में अत्याचार करने वालों की ही भांति अत्याचार का समर्थन करने वाले दोषी है। अत्याचारियों के लिये ही त्वरित न्याय और सख्त सजा जरूरी है लेकिन जन-प्रतिनिधि की निर्लज्ज बयानबाजी भी अपराध के दायरे में होनी चाहिए।

आजीवन शोषण, दमन, अत्याचार, अवांछित बर्ताव और अपमान की शिकार रही भारतीय नारी को अब ऐसे और नये-नये तरीकों से कब तक जहर के घूंट पीने को विवश होना होगा। अत्यंत विवशता और निरीहता से देख रही है वह यह क्रूर अपमान, यह वीभत्स अनादर, यह दूषित व्यवहार एवं संकुचित न्याय। न्याय एवं राजनीति की चौखट पर भी उसके साथ दोयम दर्जा एवं दुराग्रहपूर्ण सोच बदलना सर्वोच्च प्राथमिकता हो।

यदि हम सच में नारी के अशितत्व एवं अस्मिता को सम्मान देना चाहते हैं तो ईमानदार स्वीकारोक्ति, पड़ताल एवं निष्पक्ष न्याय से ही यह संभव होगा।

बड़ी चुनौती है फैक्ट्री के धमाकों को रोकना

अशोक मधुप

तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के पासमैलारम फेज एक इलाके में सोमवार को एक केमिकल फैक्टरी में हुए विस्फोट में 34 कर्मचारियों की मौत हो गई। तीन दिन पहले उत्तर प्रदेश के नोएडा के थाना फेस वन क्षेत्र स्थित डी-93 सेक्टर-दो स्थित शाम पेंट इंडस्ट्रीज केमिकल की कंपनी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि लपटें आसमान तक छूती नजर आई।

करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फायर ब्रिगेड टीम ने इस आग की घटना में किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान न होने की बात कही है। इसी 16 जून को उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव अतरासी से करीब दो किलोमीटर दूर यह फैक्ट्री चार महिलाओं की मौत हो चुकी थी। नौ घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।आरोप है कि फैक्ट्री संचालक ने पटाखे बनाने के लिए आसपास की रहने वाली महिलाओं को कम मजदूरी पर रखा था। उन्हें केवल 300 रुपये दिहाड़ी दी जाती थी। मजदूरों को न कभी ट्रेनिंग दिलाई और नही आपातस्थित से निपटने का कोई प्रशिक्षण दिया गया। फैक्ट्री में दुर्घटनाएं होने पर कुछ दिन शोर मचता है।

मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा होने के बाद सब शांत हो जाता है।दुर्घटनाएं रोकने की कोई योजना नही बनती।नही फैक्ट्री के श्रमिकों को दुर्घटना होने के समय की चुनौती बताई जाती हैं। दुर्घटना होने के समय की चुनौती के समय के लिए प्रशिक्षित भी नही किया जाता।दुर्घटना होने पर क्या किया जाए इसका भी प्रशिक्षण नही दिया जाता। फैक्ट्री लगती है किंतु उनका तकनीकि निरीक्षण नही होता।

निरीक्षण करने वाली अधिकारी पैसे के बल पर अपने आफिस में ही बैठकर रिपोर्ट बना देते है। सही मायने में फैक्ट्रियों में होने वाली दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौत का जिम्मेदार वह अमला भी है जो समय समय पर इनके सुरक्षा तंत्र का निरीक्षण करता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के महानिदेशालय फ़ैक्ट्री सलाह सेवा और श्रम संस्थान (DGFASLI) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत के पंजीकृत फ़ैक्ट्रियों में दुर्घटनाओं के कारण हर दिन औसतन तीन मज़दूरों की मौत हुई है और 11 घायल होते हैं।नवंबर 2022 में आरटीआई जवाब के अनुसार, भारत में रजिस्टर्ड फ़ैक्ट्रियों में हर साल होने वाली दुर्घटनाओं में 1,109 वर्करों की मौत हो गई और 4,000 से अधिक वर्कर घायल हुए।

ये 2017 से 2020 के बीच आंकड़ों के आधार पर है।वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि यह संख्या और भी ज्यादा है क्योंकि बड़े पैमाने पर असंगठित क्षेत्रों में होने वाले हादसों की रिपोर्ट दर्ज ही नहीं की जाती है।

निदेशालय जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट्स की रिपोर्ट, 2022 के अनुसार 2021 में, महाराष्ट्र में 6,492 खतरनाक फैक्ट्रियों में से केवल 1,551 का निरीक्षण किया गया, जिससे 23.89 प्रतिशत निरीक्षण दर प्राप्त हुई।

इसके अतिरिक्त, 39,255 पंजीकृत फैक्ट्रियों में से केवल 3,158 का निरीक्षण किया गया। इससे 8.04 प्रतिशत निरीक्षण मिली। अन्य प्रमुख औद्योगिक राज्यों में भी यह प्रवृत्ति दिखाई देती है। तमिलनाडु में सामान्य निरीक्षण दर 17.0 प्रतिशत और खतरनाक फैक्ट्रियों की निरीक्षण दर 25.39 प्रतिशत थी। गुजरात में सामान्य निरीक्षण दर 19.33 प्रतिशत और खतरनाक फैक्ट्रियों की निरीक्षण दर 19.81 मिली।। 2021 के लिए अखिल भारतीय आंकड़े सामान्य निरीक्षणों के लिए 14.65 प्रतिशत और खतरनाक फैक्ट्रियों के लिए 26.02 प्रतिशत थे। उपर्युक्त विवरण से लिया गया है।

खराब निरीक्षण दरों का एक कारण कर्मचारियों की कमी है। महाराष्ट्र में निरीक्षकों की नियुक्ति दर केवल 39.34 प्रतिशत थी।

इसमें 122 स्वीकृत अधिकारियों में से केवल 48 कार्यरत थे। गुजरात में नियुक्ति दर 50.91 प्रतिशत रही , तो तमिलनाडु में यह 53.57 प्रतिशत थी। अखिल भारतीय नियुक्ति दर 67.58 प्रतिशत थी। स्वीकृत पदों की संख्या पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या के सापेक्ष वार्षिक निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त रही है। 2021 में, अखिल भारतीय श्तर पर 953 स्वीकृत निरीक्षकों में से प्रत्येक को वार्षिक रूप से 337 पंजीकृत फैक्ट्रियों का निरीक्षण करना पड़ता है।

मई 2024 में, महाराष्ट्र इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने एक मीडिया रिपोर्ट में स्वीकार किया कि सुरक्षा निरीक्षण और प्रमाणन अक्सर ऑडिटरों और फैक्ट्री मालिकों या प्रबंधकों के बीच "समझ" के आधार पर किए जाते थे। यह संकेत देता है कि नियोक्ता भी श्रम निरीक्षकों के समान ही दोषी हैं, और भ्रष्ट प्रथाओं की "आपूर्ति पक्ष" को संबोधित करना "मांग" पक्ष के सुधार के समान ही महत्वपूर्ण है।

प्रदेश सतर पर विशिष्ट सीमा मात्रा के साथ खतरनाक रसायनों और ज्वलनशील गैसों की एक सूची स्थापित की जानी चाहिए।प्रत्येक राज्य को प्रमुख खतरे वाले कार्यस्थलों की सूची बनाए रखनी चाहिए। समें सुविधा का प्रकार, उपयोग किए गए रसायन और संग्रहीत मात्रा का विवरण हो। खतरनाक सामग्री की सूची और इन्वेंट्री को एक केंद्रीकृत डेटाबेस में संग्रहीत करें, जिस तक नियामक निकाय, आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ता, और जनता आसानी से पहुंच सकें।निरीक्षण प्रणाली को उदार बनाने के बजाय, सरकारों को आईएलओ सम्मेलन के प्रावधानों का पालन करके मजबूत श्रम बाजार शासन सुनिश्चित करना होगा। प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति और खतरनाक और रासायनिक पदार्थों के उपयोग को देखते हुए, सख्त निरीक्षणों की आवश्यकता है।

औद्योगिक आपदाओं की पुनरावृत्ति सरकार की विफलता को दर्शाती है कि उसने पिछले घटनाओं से सबक नहीं सीखा है। सुधारों और कमजोर शासन के नाम पर, राज्य अपने मूल कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता कि वह एक सुरक्षित कार्य और जीवन सुनिश्चित करे। एक प्रभावी और नैतिक श्रम निरीक्षण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सार्थक सुधारों की आवश्यकता है जो श्रमिकों और समुदाय की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता दें।

इसके साथ ही फैक्ट्री श्रमिकों का आपदा के समय सुरक्षा के उपाए, कैसे बचाव करें आदि का बार बार प्रशिक्षण देना होगा। सभी उद्योगों के निरीक्षण के लिए तकनीकि विशेषज्ञों की टीम बनानी होगी। उन्हें नियमित निरीक्षण के निर्देश करने होंगे। इससे किसी दुर्घटना होने पर मौत और घायलों का आंकड़ा कम किया जा सकता है। दुर्घटना होने के हालात में इन तकनीकि अधिकारियों की जिम्मेदारी भी फिक्स करनी होगी।देखने में आ रहा है कि निरीक्षण स्टाफ की फेक्ट्री स्वामियों से मिलीभगत होने के कारण उद्योग स्वामी प्रायः प्रशिक्षित स्टाफ नही रखते।

उत्तर प्रदेश के अमरोहा के अगवानपुर की दुर्घटना ग्रश्त पटाखा फैक्ट्री का भी ये ही कारण रहा। फैक्ट्री स्वामी ने सश्ते के चक्कर में फैक्ट्री के आसपास रहने वाली महिलाएं रख रखी थी। उन्हें वह मात्र तीन सौ रूपया रोज मजदूरी देता था। उनकी सामजिक सुरक्षा आदि का भी प्रबंध नही था।

केंद्र ही नही प्रदेश सरकारों को भी उद्योग स्वामियों को बताना होगा कि उनके यहां काम करने वाले श्रमिक और तकनीकि विशेषज्ञ देश की धरोहर है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उद्योग के साथ देश और समाज की भी है।घटना होने पर मात्र जांच के आदेश और मुआवजा देने से ही काम नही चलेगा। दुर्घटना के लिए जिम्मेदारी भी तै करनी होगी। जिम्मेदार लोगों को दंडित भी करना होगा तभी जाकर ये दुर्घटनाएं रूकेगी।

एक बात और यदि उद्योग में सुरक्षा मानक कड़े हों, उद्योग श्रमिकों को समय समय पर सुरक्षा संबधी प्रशिक्षण मिले तो दुर्घटनाएं ही न हों। हों तो मौत और घायलों की संख्या बहुत कम रहे। दुर्घटनाएं न हो तो उद्योग भी न मरे। दुर्घटनाएं होने से श्रमिकों के साथ एक प्रकार से संबधित उद्योग भी मर जाता है। अधिकतर दुर्घटनाग्रश्त उद्योग के स्वामी दुर्घटना के कारण हुए नुकसान, श्रमिकों को मुआवजा आदि देने के कारण बर्बाद हो जाते हैं।

वे दुबारा से मुश्किल से ही काम को जोड़ पाते हैं। इससे देश का एक व्यापारी,एक व्यवसायी भी एक प्रकार से मर जाता है। उसका आर्थिक रूप से मरना देश की प्रगति को भी नुकसान देता है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती आशा शर्मा द्वारा 707 मंदाकिनी टावर सेक्टर -4, वैशाली गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) भारत से प्रकाशित एवं एन.सी.आर. प्रिंटर्स, 15/19 साइट-4, साहिबाबाद इंडस्ट्रीयल एरिया जनपद गाजियाबाद से मुद्रित। **संपादक** : संजय शर्मा
फोन: 9899683800 वेबसाइट : www.ncrtoday.in **ई-मेल:** todayncr@gmail.com >> ncrtoday@hotmail.com **RNI-**UPHIN/2009/30721

संक्षिप्त समाचार

कुएं में मिली 21 वर्षीय युवक की लाश, चार दिन से था लापता

आगरा , एजेंसी। आगरा के थाना हरीपर्वत क्षेत्र से चार दिन से लापता हुए युवक का शव हाथरस में कुएं में मिला। वह 27 जून को दोस्तों के साथ एक्टिवा से निकला था। सीसीटीवी में युवक अकेला जाता हुआ नजर आया था। जानकारी मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए। थाना हरिपर्वत में गुमशुदी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने दोनों दोस्तों को पूछताछ के लिए लिया हिरासत में लिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।

हाथरस के कोतवाली सहपऊ क्षेत्र के गांव नगला महासुख के निकट बाजरा के खेतों के बीच में बने हुए एक सूखे कुएं में 21 वर्ष कुनाण प्रजापति का शव मिला है। मृतक के चाचा देवकीनंदन ने बताया कि उनका भतीजा 27 जून को सुबह घर से काम के लिए निकला था। वह पिता के साथ ही हलवाई का काम करता था। शाम तक वापस न आने पर 28 जून को उन्होंने कोतवाली हरीपर्वत जनपद आगरा में युवक की गुमशुदगी दर्ज कराई थी।

30 जून की रात करीब 2 बजे पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम हाथरस के लिए भिजवा दिया है। मृतक के चाचा के अनुसार कि उनके परिवार की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। सीओ सादाबाद हिमांशु माथुर का कहना है कि हरीपर्वत कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई गई है। वहां की पुलिस ही इस मामले की जांच करेगी।

चोरों ने शिव मंदिर को बनाया निशाना, शिवलिंग और त्रिशूल उठा ले गए चोर; जांच में जुटी पुलिस

मिर्जापुर , एजेंसी। मिर्जापुर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के रैकरी गांव स्थित प्राचीन शिव मंदिर से सोमवार की रात चोर शिवलिंग ही चोरी कर ले गए। साथ ही पीतल का त्रिशूल भी चोर उठा ले गए। अन्य मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। मंगलवार की सुबह जब अरविंद राणा मंदिर में पूजा करने के लिए गए तो चोरी की जानकारी हुई।

उन्होंने घटना की सूचना राजगढ़ थाने में दी। मंदिर में एक वर्ष के अंदर चोरी की यह दूसरी घटना है। पिछले वर्ष चोरों ने सफेद पत्थर के शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया था। जिसके बाद काले पत्थर का शिवलिंग स्थापित किया गया। अब तक मंदिर में शिवलिंग चोरी व क्षतिग्रस्त करने वालों का पता नहीं चल सका है। मंदिर में चोरी से ग्रामीणों में आक्रोश है। थानाध्यक्ष रणविजय सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है।

महिला की मौत पर परिजनों का हंगामा, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप

शव सड़क पर रख कर प्रदर्शन

बलिया , एजेंसी। बलिया जिले के सिकंदरपुर कस्बा के बस स्टेशन चौराहे के समीप मंगलवार की सुबह जमकर हंगामा हुआ। यहां परिजनों ने 26 वर्षीय महिला माधुरी का शव दुबरी चौधरी के कटरा के बाहर रख दिया और न्याय की मांग करने लगे। मृतका के पिता रामाशीष कनौजिया, निवासी करमौता गांव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पुत्री की मौत एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय लापरवाही के कारण हुई है।

ये है पूरा मामला: रामाशीष के अनुसार, 26 जून को उनकी पुत्री माधुरी (25) जो ताड़ी बड़ागांव थाना नगरा निवासी राजेश कनौजिया की पत्नी थी, उसको उर्मिला वर्मा के कहने पर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में मौजूद महिला चिकित्सक और उनके स्टाफ ने बिना परिजनों की अनुमति के बाहर से एक चिकित्सक को बुलाकर ऑपरेशन कर दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि ऑपरेशन के बाद माधुरी की हालत लगातार बिगड़ती रही। 27 जून से ही वे चिकित्सकों से लगातार आग्रह करते रहे कि उनकी बेटी को बेहतर इलाज के लिए कहीं और रेफर किया जाए।

आयुष विश्वविद्यालय का राष्ट्रपति ने किया लोकार्पण

बोलीं- पारंपरिक चिकित्सा का है आधुनिक केंद्र

गोरखपुर , एजेंसी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ने मंगलवार को आयुष विश्वविद्यालय के लोकार्पण किया। बोलीं, गोरखनाथ ने इस क्षेत्र को ऊर्जा से समृद्ध किया है। नाथ पंथ के योगी जन और स्वतंत्रता संग्राम के बंधू सिंह, बिस्मिल की ये धरती है। गीता प्रेस और यहां की की पुस्तकें विश्व में विख्यात हैं और उनका एक अलग धार्मिक महत्व है। औद्योगिक क्षेत्र गीडा की गतिविधियों का भी तेजी से विस्तार हो रहा है।

लोकार्पण के दौरान उन्होंने कहा कि ये विश्वविद्यालय पारंपरिक चिकित्सा का आधुनिक केंद्र है। मेडिकल एजुकेशन और चिकित्सा के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इस विश्वविद्यालय से करीब 100 कालेज लाभांवित हो रहे हैं। आयुष पद्धति से जुड़े रोजगार की शिक्षा भी दी जाएगी।

इस उत्कृष्ट विश्वविद्यालय को दिशा प्रदान करने के लिए सीएम को धन्यवाद भी दिया। बोलीं, योगी कहते हैं कि योग करने से आठ घंटे की नींद तीन घंटे में पूरा होती है। कहा, पीएम ने योग को अंतरराष्ट्रीय मंच दिया। योग सभी को करना चाहिए। स्वास्थ्य ही संपदा है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो 2047 तक विकसित भारत का सपना।

स्वास्थ्य से ही पूरा होगा। भारत ऋषियों की भूमि है। 300-400-200 साल जीते थे। शरीर पंचतत्व से तैयार हुआ है। आज हमारे पास संसाधन, बहुत सी सुविधाएं। स्वस्थ रहने का वैज्ञानिक पद्धति आयुर्वेद में बताया गया है। ये अच्छा है। हमें पुरानी परंपराओं को फालो करना पड़ेगा। दिनचर्या, संतुलित आहार, विहार व विचार का महत्व।

आयुर्वेद हमारी धरती से जुड़ा है। हमारे, खेत-जंगलों में औषधियों काख़जाना है। आयुर्वेद का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। जर्मनी में विकसित हुई होम्योपैथी को देश ने पूरी तरह से अपना लिया है। गुरु गोरखनाथ ने योग की परंपरा को फिर से जगाया था। आयुष पद्धति पर आधारित चिकित्सा की लोकप्रियता बढ़ रही है।

सीएम योगी ने कहा- हर जिले में बनाएंगे 100 बेडेड आयुष वेलनेस सेंटर, रोजगार का भी बनेगा साधन

गोरखपुर , एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश को पहले आयुष विश्वविद्यालय का उपहार देने के बाद सरकार जन आरोग्यता के लिए हर जिले में कम से कम 100 बेडेड का आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाएगी। यहां पंचकर्म, क्षारसूत्र जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं को भी उपलब्ध कराया जाएगा।

इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश के उन छह मंडलों में मंडल मुख्यालय स्तर पर एक-एक आयुष महाविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है जो अब तक ऐसे महाविद्यालय की सुविधा से वंचित थे। सीएम योगी मंगलवार को उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय (महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय) के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु और अति विशिष्ट अतिथि राज्यपाल आनंदी बेन पटेल का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान मर केंद्र और प्रदेश सरकार सम्पूर्ण आरोग्यता की दिशा में निरंतर कार्य कर रही हैं। 2014 के पूर्व भारत की आरोग्यता की प्राचीन पद्धतियों, सुविधाओं को वैश्विक मान्यता नहीं मिल पाई थी।

2014 में प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथ, नेचुरोपैथी, सिद्धा को मिलाकर आयुष मंत्रालय बनाया और परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को नया मंच दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय पीएम मोदी की प्रेरणा से सम्पूर्ण आरोग्यता के लिए बनाया गया उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है। लोकार्पण के साथ अब इस विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी। लोगों को आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, योग, नेचुरोपैथी, सिद्धा आदि विधाओं की चिकित्सा सेवा का लाभ मिलेगा। यह विश्वविद्यालय आयुष के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बड़े केंद्र के रूप में भी आगे बढ़ेगा। सीएम योगी ने कहा कि किसानों और नौजवानों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने में भी आयुष विश्वविद्यालय की बड़ी भूमिका होगी। इस विश्वविद्यालय के जरिये औषधीय पौधों की खेती रोजगार बढ़ाने में मददगार होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को हेल्थ टूरिज्म के नए रूप में आकर्षित करने में भी आयुष विश्वविद्यालय निर्णायक साबित होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आयुष विश्वविद्यालय हेल्थ टूरिज्म का नया डेस्टिनेशन बनेगा।

नवनाथ और चौरासी सिद्धों की परंपरा से जुड़ा है आयुर्वेद का रस शास्त्र

आयुष विश्वविद्यालय के लोकार्पण समारोह में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुर्वेद और नाथपंथ के आपसी जुड़ाव का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद में रस शास्त्र, धातु विज्ञान का आविष्कार नवनाथ तथा चौरासी सिद्धों की परंपरा से जुड़ता है और, इसे व्यवस्थित करने का श्रेय महायोगी गुरु गोरखनाथ को दिया जाता है।

एक गांव-एक औषधीय पौधा' की शुरुआत करें किसान : आनंदी बेन पटेल- प्रदेश के पहले, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के लोकार्पण समारोह में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने किसानों का आह्वान किया कि वे 'एक गांव-एक औषधीय पौधा' अभियान की शुरुआत करें। आयुष विश्वविद्यालय के रूप में पूर्वांचल में आयुर्वेद का बड़ा सेंटर शुरू हो रहा है और इसके माध्यम से औषधीय खेती को भी बढ़ावा मिलेगा।

मानसून की बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत, मगर उमस ने फिर ली करवट

मेरठ , एजेंसी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आखिरकार मानसून ने दस्तक दे दी है। रविवार रात और सोमवार सुबह हुई बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी। लंबे इंतजार के बाद जब बारिश की बूंदें जमीन से टकराईं, तो मौसम ठंडा जरूर हुआ, मगर उमस की चुपके से वापसी भी देखने को मिली। मोदीपुरम स्थित भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ. एम. शमीम ने जानकारी दी कि अगले दो दिन तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। उनका कहना है कि यह बारिश किसानों के लिए भी वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि इससे धान की बुवाई की तैयारी कर रहे किसानों को राहत मिलेगी। बारिश से वायु गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (त्त्क्ष्) 50 से नीचे आ गया है और शहर की हवा पहले से ज्यादा साफ महसूस की जा रही है। मेरठ समेत आसपास के जिलों में भी यही हालात हैं। हालांकि बारिश के चलते कुछ इलाकों में जलभराव की समस्या भी सामने आई है, लेकिन समग्र रूप से मौसम का यह बदलाव राहत भरा है।

राजा जी हवेली में घुसी बेकाबू कार, 4 को रौंदा

हापुड़ , एजेंसी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे से अचानक एक कार बेकाबू होकर होटल में घुस गई। कार ने चार लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि प्रेमिका समेत तीन लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

जानकारी के अनुसार, हापुड़ जिले के थाना बाबूगढ़ इलाके के कुचेसर रोड़ चौपला स्थित राजा जी हवेली में यह घटना सोमवार रात साढ़े दस बजे हुई है। बुलंदशहर जिले के फरादपुर का रहने वाला युवक बाइक से प्रेमिका का बर्थडे विश करने के लिए होटल में पहुंचा था।

इसी दौरान हाईवे से एक बेकाबू कार होटल में घुस गई। यहां कुर्सी पर बैठे प्रेमी-प्रेमिका समेत चार लोगों को बेकाबू कार ने रौंद दिया। हादसे में प्रेमी अजितपाल की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि प्रेमिका समेत दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं। हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया। मृतक दिल्ली जल बोर्ड में संविदा पर नौकरी करता है। वह सोमवार शाम पांच बजे मां को घर से बताकर आया था कि वह युवती की बर्थ-डे पार्टी में शामिल होने जा रहा है। मृतक के परिजन मौके पर पहुंच गए हैं। परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका भी जाहिर की है। मृतक युवक तीन बहनों में अकेला था। प्रेमिका गढ़मुक्तेश्वर इलाके की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने फरार कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर उसकी जांच शुरू कर दी है।

पुरानी बीमारी बताकर क्लेम देने से इंकार नहीं कर सकती बीमा कंपनी

-आयोग ने कहा, हायपरटेंशन जीवनशैली से जुड़ी बीमारी

✷ एनसीआर टुडे. ग्रेटर नोएडा ✷

पुरानी बीमारी बताकर बीमा कंपनी क्लेम देने से इंकार नहीं कर सकती। जिला उपभोक्ता आयोग ने यह टिप्पणी करते हुए एक मामले में उपभोक्ता को 6 फीसदी ब्याज समेत क्लेम राशि का 30 दिन में भुगतान करने का आदेश दिया है। पांच हजार रुपये वाद व्यय भी देना होगा।

नोएडा के सेक्टर 5 हरौला निवासी विकास कुमार ने अपने पिता ज्ञानेंद्र सिंह व माता जगरती के नाम से एक हेल्थ पॉलिसी ली थी। 6 जुलाई 2021 को 24507 रुपये प्रीमियम का भुगतान केयर हैल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को किया। 5 जुलाई 2022 तक पॉलिसी वैध थी। उनके पिता को 10 फरवरी 2022 को सीने में दर्द हुआ। दर्द के दौरान सांस लेने में दिक्कत हुई। उनको तुरंत ही कैलाश अस्पताल नोएडा में भर्ती किया गया। पॉलिसी से स्वीकृति मांगी गई। उसके साथ ही इलाज शुरू कर दिया। 17 फरवरी 2022 तक इलाज में 178537 रुपये का खर्च हुआ। पॉलिसी होने के बाद भी उनको नकद में भुगतान करना पडा।

10 जुलाई 2023 को बीमा कंपनी से जानकारी मिली की उनका क्लेम निरश्त कर दिया। क्लेम नहीं मिलने पर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया।

मामले में सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा के समक्ष बीमा कंपनी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पॉलिसी लेने के दौरान अपने प्रपोजल फार्म में आवश्यक तथ्यों को छुपाया गया था। इस कारण क्लेम निरश्त किया गया।

आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि प्रपोजल फार्म में हायरपर टेंशन का उल्लेख नहीं करने से ही बीमा कंपनी प्रतिपूर्ति दावे को अस्वीकार नहीं कर सकती है। आयोग ने 6 फीसदी ब्याज समेत 178537 रुपये का 30 दिन में भुगतान करने का आदेश दिया है। पांच हजार रुपये वाद व्यय के भी देने होंगे।

चोरी के मामले में दोषी को तीन साल की सजा

✷ एनसीआर टुडे. ग्रेटर नोएडा ✷

थाना कासना में दर्ज एक पुराने चोरी के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। मामला थाना कासना क्षेत्र में वर्ष 2015 में दर्ज किया गया था।

इसमें आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले में आरोपी ईशाक उर्फ लल्ला निवासी कस्बा थाना पाकबड़ा मुरादाबाद को नामजद किया गया था।

थाना कासना पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन इकाई की ओर से मामले में प्रभावी ढंग से विवेचना एवं पैरवी की गई। साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष यह सिद्ध किया कि आरोपी ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और चोरी की संपत्ति उसके पास से बरामद हुई थी। आरोप सिद्ध होने के बाद न्यायालय ने आरोपी ईशाक उर्फ लल्ला को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

चोरी की कारों संग पकड़े गए दो आरोपियों को मिली जमानत

फाईल फोटो

✷ एनसीआर टुडे. ग्रेटर नोएडा ✷

सेक्टर-113 थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चोरी की कारों समेत पकड़े गए दो आरोपी असलम व मकसूर उर्फ रिहान उर्फ राहुल को जिला सत्र न्यायालय ने शर्तों के साथ जमानत दे दी है।

आरोप है कि 4 जून 2025 की रात को पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्तों को पर्थला डूब क्षेत्र के कब्रिश्तान के पास गिरफ्तार किया गया था।

इनके पास से इनोवा, किया सैल्टोस, केटा, स्विफ्ट कारें, अवैध हथियार, कार के लॉक तोड़ने के उपकरण और अन्य सामान बरामद हुआ था। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपियों को झूठा फंसाया गया है और उन्हें पहले ही 27 मई से पुलिस ने अवैध रूप से उठाकर रखा था। जिसकी शिकायत आरोपी की पत्नी ने जिलाधिकारी को दी थी। साथ ही यह भी कहा गया कि बरामदगी के कोई स्वतंत्र गवाह नहीं हैं। आरोपी कई मामलों में पहले ही मजिस्ट्रेट न्यायालय से जमानत पा चुके हैं।

सरकारी अधिवक्ता ने याचिका का विरोध किया, लेकिन अदालत ने अभियुक्तों के जेल में निरुद्ध रहने, स्वतंत्र गवाहों के अभाव और पूर्व में मजिस्ट्रेट से मिली जमानत को देखते हुए यह याचिका मंजूर कर ली।

280 विद्यालयों के विद्यार्थी दूसरे स्कूलों में हुए शिफ्ट, 62 स्कूलों में घटी विद्यार्थियों की संख्या

अलीगढ़ , एजेंसी। 30 जून को अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा विभाग के और 280 विद्यालयों का दूसरे स्कूलों में विलय हो गया। इन स्कूलों के बच्चों को एक किमी के दायरे वाले स्कूलों में शिफ्ट किया गया है। इस तरह अब तक 465 विद्यालयों का विलय हो चुका है। जिले में 2115 में से 665 विद्यालयों का विलय होना है। इन स्कूलों के 26 हजार बच्चे दूसरे विद्यालयों में समायोजित होंगे। तीन चरण में अब तक 465 स्कूलों का विलय हो गया है। विकास खंड टप्पल, चंडौस, जवां, खैर, लोधा, धनीपुर, अकराबाद, इगलास, गोंडा, अतरौली, बिजौली, गंगीरी में 22-22 और अलीगढ़ में 16 विद्यालयों का विलय हो गया है। इनमें करीब एक हजार बच्चे दूसरे विद्यालय में समायोजित किए गए हैं। जिले में 665 विद्यालय ऐसे हैं, जिसमें 50 से कम बच्चे पंजीकृत हैं। पहले चरण में 160, दूसरे चरण में 25 और तीसरे चरण में 280 विद्यालयों का दूसरे विद्यालयों में विलय हो गया। विद्यालयों में 50 से कम विद्यार्थी और शिक्षक भी दूसरे विद्यालयों में जाएंगे।

बाल वाटिका में बदलेगा विद्यालय

जिले के 665 विद्यालय अब बाल वाटिका में नजर आएंगे। इन विद्यालयों में 50 से कम बच्चे नामांकित है। बाल वाटिका में 3 से 6 साल आयु वर्ग के बच्चे पढ़ेंगे और खेलेंगे। बच्चों को पढ़ाने के लिए 196 विशेष शिक्षक की तैनाती की गई है। इस संबंध में बीएसए डॉ. राकेश कुमार सिंह ने बताया कि बाल वाटिका में खेलकूद के सामान और लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी। कोई भी विद्यालय न तो बंद हो रहा है और न ही शिक्षकों की सेवा पर खतरा मंडरा रहा है।

62 स्कूलों में घटी विद्यार्थियों की संख्या, सभी स्टाफ की वेतन वृद्धि रोकी

पिछले एक साल में अलीगढ़ जिले के 62 परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में गिरावट आई है। इस पर सभी स्टाफ की वेतन वृद्धि रोक दी गई है। विकास खंड जवां के प्राथमिक विद्यालय भगवानगढ़ी में 488 में से 182 बच्चे घट गए। प्राथमिक विद्यालय सिधौली खुर्द बिजौली में 242 में से 126, प्राथमिक विद्यालय उमरी चंडौस में 268 में से 126, प्राथमिक विद्यालय पिलखना अकराबाद में 322 में 121, प्राथमिक विद्यालय रठगांव जवां में 479 में से 120, प्राथमिक विद्यालय नगला मानसिंह लोधा में 535 में से 117, उच्च प्राथमिक विद्यालय कजरौठ में 339 में से 112, उच्च प्राथमिक विद्यालय शाहजहांबाद में 259 में से 105, प्राथमिक विद्यालय क्वार्सी में 358 में से 103 बच्चे घट गए। इसी तरह अन्य विद्यालयों में 98 से लेकर चार बच्चों के नामांकन में कमी आई है। इस संबंध में बीएसए डॉ. राकेश कुमार सिंह ने बताया कि तीन वर्षों में भेजे गए कंपोजिट ग्रांट व एमडीएम की धनराशि के लिए जांच दिए गए थे, जिनकी जांच चल रही है।

अनुपस्थित 40 शिक्षकों को नोटिस

अलीगढ परिषदीय विद्यालयों में सात से 19 मई तक हुए निरीक्षण में 40 शिक्षक अनुपस्थित मिले। इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विभाग के बीईओ, मेडिकल ऑफिसर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर ने विकास खंड इगलास, गोंडा, धनीपुर, खैर, अकराबाद, अलीगढ़, बिजौली, लोधा, जवां के विद्यालयों में निरीक्षण किया था। निरीक्षण में गैरहाजिर मिले सहायक अध्यापक, शिक्षामित्र, अनुदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा गया है।

बलिया में तेज रफ्तार का कहर: टक्कर के बाद पिकअप में फंसी बाइक

बलिया , एजेंसी। बलिया जिले के सिकंदरपुर बस स्टेशन चौराहे पर सुबह बेल्थरा रोड के तरफ से आ रही अनियंत्रित पिकअप यूनियन बैंक के समीप एक बाइक सवार को रौंद डाला। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसकी बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है।

15 फीट तक घसीटता गया युवक; मौत से लड़ रहा जंग

घायल युवक की पहचान धर्मेंद्र पुत्र कैलाश निवासी किला कोहना सिकंदरपुर के रूप में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बेल्थरा रोड की दिशा से तेज गति में आ रही पिकअप पर हरी सब्जियों का बोझ लदा था। पिकअप जैसे ही यूनियन बैंक के सामने पहुंची, चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और सामने से आ रही बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पिकअप के नीचे फंस गई और करीब 10 से 15 फीट तक घसीटती चली गई। टक्कर के बाद बाइक के परखच्चे उड़ गए और उसका अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय नागरिकों की मदद से घायल बाइक सवार धर्मेंद्र को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बलिया जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।

उधर, घटना के बाद चालक पिकअप वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पिकअप को कब्जे में ले लिया और आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी।

बुमराह आउट कुलदीप IN...

इंडिया-इंग्लैंड दूसरे टेस्ट में होंगे ये बड़े बदलाव

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी पांच मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा मुकाबला बुधवार, 2 जुलाई से बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा. इससे पहले मंगलवार को भारत के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने टीम इंडिया की संभावित रणनीति और बदलावों को लेकर अहम जानकारी दी. रयान टेन डोशेट ने साफ कहा कि दूसरे टेस्ट में कम से कम दो बदलाव होंगे. टीम बर्मिंघम टेस्ट में नए कॉम्बिनेशन के साथ उतर सकती है.

बुमराह को आराम, लॉर्ड्स टेस्ट में वापसी संभव

रयान टेन डोशेट ने बताया कि भारत के स्टार तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह को बर्मिंघम टेस्ट में आराम दिया जा रहा है. वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत उन्हें यह ब्रेक दिया गया है और वह तीसरे टेस्ट (लॉर्ड्स में) वापसी के लिए उपलब्ध रहेंगे.बुमराह ने पहले टेस्ट में पांच विकेट लेकर बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन लगातार क्रिकेट को देखते हुए उन्हें ब्रेक देना ज़रूरी समझा गया.

जायसवाल स्लिप फील्डिंग से बाहर, लगातार कैच ड्रॉप्स पड़े भारी

पहले टेस्ट में युवा सलामी बल्लेबाज़ यशस्वी जैसवाल ने चार कैच छोड़े थे, जिससे इंग्लैंड को बड़े रन बनाने में मदद मिली. अब टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि जायसवाल को स्लिप कॉर्डन से हटा दिया गया है और उन्हें फिलहाल आउटफील्ड में लगाया जाएगा. जायसवाल ने पहले टेस्ट की पहली पारी में शतक ज़रूर लगाया था, लेकिन फिल्डिंग में उनकी गलती टीम पर भारी पड़ी.

शार्दुल ठाकुर की जगह नीतीश कुमार रेड्डी की एंट्री तय

पिछले मैच में शार्दुल ठाकुर गेंद और बल्ले दोनों से खास प्रभाव नहीं डाल सके. अब उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर किया जा रहा है और उनकी जगह आंध्र प्रदेश के युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में शामिल किया जा सकता है.

वहीं, बर्मिंघम की पिच पर इस बार गर्म मौसम और सूखी सतह को देखते हुए भारत दो स्पिन गेंदबाज़ों को प्लेइंग इलेवन में शामिल कर सकता है. रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर- इन तीनों में से दो को मौका मिलने की संभावना है. पहले टेस्ट में रवींद्र जडेजा को अकेले स्पिनर के रूप में खिलाया गया था, लेकिन अब बदलाव की तैयारी है. रायन टेन डोशाटे ने कुलदीप यादव की नेट बॉलिंग की तारीफ की और कहा कि वो शानदार लय में हैं और विकेट लेने की भूख के साथ मैदान पर उतरने को तैयार हैं. भारत को पहले टेस्ट में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था.

इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 की घोषणा की

आर्चर टीम में नहीं

नई दिल्ली, एजेंसी। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए सोमवार 30 जून को अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा की, जो बुधवार से बर्मिंघम के एजबेस्टन में शुरू होगा। भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने जीत दर्ज करते हुए पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में बढ़त बनाई थी। बेन स्टोक्स की अगुआई वाली टीम में दूसरे मैच के लिए टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उंगली की चोट से उबरने के बाद इंग्लैंड की टीम में शामिल किए गए तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को शुरुआती लाइनअप में शामिल नहीं किया गया है। आर्चर परिवार में इमरजेंसी के कारण एजबेस्टन में सोमवार के अभ्यास सत्र का हिस्सा नहीं बन पाए। वहीं जोश टंग, ब्रायडन कार्स और क्रिस वोक्स फ्रंटलाइन तेज गेंदबाज के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दूसरी तरफ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दूसरे मैच के लिए आराम दिए जाने की उम्मीद है जिससे भारत की लाइनअप में बदलाव देखने को मिल सकता है। बुमराह के अलावा भारतीय टीम में स्पिनर कुदलीप यादव को भी शामिल करने की बात सामने आ रही है जो लंदन में प्रभावी साबित हो सकते हैं।

इंग्लैंड की प्लेइंग 11

जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), क्रिस वोक्स, ब्रायडन कार्स, जोश टंग, शोएब बशीर।

हॉकीः

यूरोप दौरे पर इंडिया-ए की कमान संभालेंगे संजय

नई दिल्ली, एजेंसी। हॉकी इंडिया ने मंगलवार को यूरोप के आगामी दौरे के लिए इंडिया-ए पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। यह दौरा 8 से 20 जुलाई तक चलेगा। भारत के इस यूरोप दौरे में कुछ शीर्ष यूरोपीय टीमों के खिलाफ कुल आठ मैच खेले जाएंगे, जिसका उद्देश्य उभरते और अनुभवी खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव प्रदान करना है। इंडिया-ए टीम आयरलैंड, फ्रांस और नीदरलैंड के खिलाफ दो-दो मैच खेलेगी, जबकि उसे इंग्लैंड और बेल्जियम के खिलाफ एक-एक मुकाबला खेलना है। 20 सदस्यीय टीम में अनुभवी और होनहार युवा खिलाड़ियों का मिश्रण है, जिन्होंने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सर्किट में प्रभावित किया है। इंडिया-ए टीम की कप्तानी संजय करेंगे, जबकि मोइरांगथेम रबीचंद्र सिंह उप-कप्तान होंगे। भारत की टीम में गोलकीपर पवन और मोहित होनेनहल्ली शशिकुमार और डिफेंडर प्रताप लाकड़ा, वरुण कुमार, अमनदीप लाकड़ा, प्रमोद और संजय शामिल हैं। मिडफील्डर्स में पूवन्ना चंदुरा बॉबी, मोहम्मद राहील मौसीन, मोइरंगथेम रबीचंद्र सिंह, विष्णुकांत सिंह, प्रदीप सिंह और राजिंदर सिंह मौजूद हैं, जबकि फॉरवर्ड लाइन-अप में अंगदबीर सिंह, बॉबी सिंह धामी, मनिंदर सिंह, वेंकटेश केंचे, आदित्य अर्जुन लालगे, सेल्वम कार्ति और उत्तम सिंह हैं। स्टैंडबाय खिलाड़ियों की लिस्ट में गोलकीपर अंकित मलिक, डिफेंडर सुनील जोजो और फॉरवर्ड सुदीप चिरमाको शामिल हैं। यूरोप के दौरे पर टीम को शिवेंद्र सिंह ट्रेनिंग देंगे, जो पुरुष टीम के असिस्टेंट कोच भी हैं। शिवेंद्र सिंह बेहद अनुभवी हैं। वह आक्रामक खेल पर खासा ध्यान देते हैं। यह दौरा हॉकी इंडिया के दीर्घकालिक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारतीय हॉकी सितारों की अगली पीढ़ी को अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का मौका देना है।

यूरोप दौरे के लिए भारत-ए की टीमः

गोलकीपरः पवन, मोहित होनेनहल्ली शशिकुमार।

डिफेंडरः प्रताप लाकड़ा, वरुण कुमार, अमनदीप लाकड़ा, संजय (कप्तान) और प्रमोद।

मिडफील्डरः पूवन्ना चंदूरा बॉबीमोहम्मद राहील मौसीन, मोइरांगथेम रबीचंद्र सिंह (उप-कप्तान), विष्णुकांत सिंह, प्रदीप सिंह और राजिंदर सिंह।

फॉरवर्डः अंगदबीर सिंह, बॉबी सिंह धामी, मनिंदर सिंह, वेंकटेश केंचे, आदित्य अर्जुन लालगे, सेल्वम कार्ति और उत्तम सिंह।

स्टैंडबायः अंकित मलिक (गोलकीपर), सुनील जोजो (डिफेंडर) और सुदीप चिरमाको (फॉरवर्ड)।

वर्ल्ड क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड चैम्पियनशिप 2025:

इंग्लैंड का क्लीन स्वीप, मार्क गुडलिफ बने पहले विश्व विजेता

लंदन, एजेंसी। लंदन के प्रतिष्ठित नेहरू सेंटर में आयोजित पहले वर्ल्ड क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड चैम्पियनशिप में शब्दों की चतुराई और मानसिक तीव्रता का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां टीम इंग्लैंड ने शीर्ष तीनों स्थानों पर कब्जा करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 13 बार टाइम्स क्रॉसवर्ड चैंपियनशिप जीत चुके मार्क गुडलिफ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए WCCC 2025 विश्व कप विजेता का खिताब अपने नाम किया। कॉलिन थॉमस को प्रथम उपविजेता घोषित किया गया, जबकि जॉन हेंडरसन ने तीसरा स्थान प्राप्त कर इंग्लैंड की प्रभुत्वता को और मजबूत किया। प्रतियोगिता दो चरणों में आयोजित हुई।

विंबलडन 2025:

विंबलडन के पहले दौर में उलटफेर का शिकार हुए मेदवेदेव, बेंजामिन बोंजी ने हराया

नई दिल्ली, एजेंसी। मेदवेदेव इससे पहले 2017 में लगातार दो ग्रैंड स्लैम के शुरुआती दौर में हारे थे। वह उस साल ऑस्ट्रेलियाई ओपन और फ्रेंच ओपन के पहले दौर में हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हुए थे। नौवीं वरीयता प्राप्त दानिल मेदवेदेव सोमवार को विंबलडन के शुरुआती दौर में 64वीं रैंकिंग वाले बेंजामिन बोंजी से 7-6 (2), 3-6, 7-6 (3), 6-2 से हार के साथ उलटफेर का शिकार बने। पिछले साल विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले मेदवेदेव लगातार दूसरे ग्रैंड स्लैम के पहले दौर से बाहर हो गए हैं। रूस के यह खिलाड़ी इससे पहले फ्रेंच ओपन में भी पहले दौर से बाहर हो गए था। उन्हें साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियाई ओपन में दूसरे दौर में शिकस्त का सामना करना पड़ा था।

2017 में भी लगातार दो ग्रैंड स्लैम के शुरुआती दौर में हारे

मेदवेदेव इससे पहले 2017 में लगातार दो ग्रैंड स्लैम के शुरुआती दौर में हारे थे। वह उस साल ऑस्ट्रेलियाई ओपन और फ्रेंच ओपन के पहले दौर में हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हुए थे। मेदवेदेव इस साल पेरिस में कैमरून नॉरी से पांच सेट के मैच में हार गए थे। वह 2023 में फ्रेंच ओपन की पहली बाधा पार करने में नाकाम रहे थे। उस समय दूसरी वरीयता प्राप्त मेदवेदेव को पहले दौर में क्वालिफायर थियागो सेबॉथ वाइल्ड ने हराया था। वाइल्ड की उस समय विश्व रैंकिंग 172 थी।

क्लब विश्व कपः

मैनचेस्टर सिटी को हराकर क्वार्टर फाइनल में अल हिलाल

ऑरलैंडो (अमेरिका), एजेंसी। मार्कोस लियोनार्डो ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अल हिलाल को मैनचेस्टर सिटी पर 4-3 से जीत दिलाई। इसी के साथ टीम ने फीफा क्लब विश्व कप क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बर्नार्डो सिल्वा ने नौवें मिनट में ही गोल दागा। इसके बाद दोनों टीमों ने लगातार कोशिशें कीं, लेकिन कोई और गोल इस हाफ में नहीं आया। दूसरे हाफ में मार्कोस लियोनार्डो (46) और मैल्कम (52) ने गोल दागकर अल-हिलाल को 2-1 से आगे कर दिया, लेकिन तीन मिनट बाद ही एरलिंग हैलैंड (55) ने गोल दागकर जल्दी ही मैनचेस्टर सिटी को बराबरी पर ला दिया।

अल-हिलाल ने अतिरिक्त समय में कलिडौ कौलीबाली (94) की मदद से फिर से बढ़त हासिल की, लेकिन फिल फोडेन के 100वें सिटी गोल ने सिटी को बराबरी पर ला दिया। लियोनार्डो अल-हिलाल के लिए मैच विजेता साबित हुए। लियोनार्डो ने 112वें मिनट में गोल दागकर अल-हिलाल को 4-3 से आगे कर दिया। मैच के बाद कलिडौ कौलीबाली ने कहा, हम जानते थे कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक के खिलाफ एक कठिन खेल था। हम अपने विचारों, अपनी प्रतिभा, अपनी ताकत को दिखाना चाहते थे। मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छा खेल खेला। रक्षात्मक रूप से हम बहुत मजबूत थे।

आक्रामक रूप से हमने सभी मौकों का फायदा उठाया, इसलिए हम खुश हो सकते हैं। अल हिलाल अब शुक्रवार को सेमीफाइनल में फ्लुमिनेंस एफसी से भिड़ेगा। यह मुकाबला ऑरलैंडो के कैम्पिंग वर्ल्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। फ्लुमिनेंस एफसी की टीम इंटर के खिलाफ 2-0 से मुकाबला जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची है।

दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबलों को देखें, तो पाल्मेरास की चेल्सी से भिड़ंत होगी, जबकि पीएसजी की टीम बेयर्न के खिलाफ सेमीफाइनल में पहुंचने के इरादे से उतरेगी। सेमीफाइनल मुकाबले नौ और दस जुलाई को खेले जाने हैं। खिताबी मैच 14 जुलाई को होगा।

असाधारण प्रदर्शन करने के लिए सचिन तेंदुलकर से प्रेरणा लेता हूंः नीरज चोपड़ा

बेंगलुरू, एजेंसी। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने कहा कि वह चुनौतियों का सामना करने के बावजूद असाधारण प्रदर्शन करने की भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की महाशक्ति को पाना चाहेंगे।

हाल ही में पेरिस डायमंड लीग और ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक मीट जीतने वाले नीरज, नीरज चोपड़ा क्लासिक भाला फेंक प्रतियोगिता के उद्घाटन संस्करण के साथ इतिहास रच रहे हैं, जो विश्व एथलेटिक्स 'ए' श्रेणी की प्रतियोगिता है, जो भारत में होने वाली अपनी तरह की पहली प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन 5 जुलाई को बेंगलुरु के श्री कांतीरवा स्टेडियम में किया जाएगा। बात करते हुए, जब उनसे पूछा गया कि भाला फेंकने के लिए वह किस क्रिकेटर की महाशक्ति को पाना चाहेंगे, तो मौजूदा विश्व चैंपियन ने तेंदुलकर का नाम लिया। चोपड़ा ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, सचिन तेंदुलकर। उन्होंने इतने सालों तक हमारे देश का बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व किया और हमारे लिए कई रिकॉर्ड बनाए। जिस तरह से उन्होंने कई महान गेंदबाजों की चुनौतियों का सामना किया और फिर भी असाधारण प्रदर्शन किया - मैं भी वैसा ही करना चाहूंगा।

इससे मुझे शांत मानसिकता के साथ आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। 27 वर्षीय भाला फेंक स्टार ने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के महान तेज गेंदबाज ब्रेट ली, जो क्रिकेट में अपना नाम बनाने से पहले भाला फेंकते थे, और भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भाला फेंकने में सक्षम होंगे। मैंने सुना है कि ब्रेट ली एक भाला फेंकने वाले थे। मुझे लगता है कि वह भाला अच्छी तरह से फेंक सकते थे, खासकर जब वह अपने चरम वर्षों में थे। मैं जसप्रीत बुमराह के साथ भी भाला फेंकना

चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि वह मुझे कुछ गेंदबाजी कौशल सिखाएंगे। हालांकि गेंदबाजी और भाला फेंकना दोनों ही अलग-अलग हैं। मैं बुमराह से सीखना चाहूंगा। चोपड़ा ने कहा कि भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का मशहूर हेलीकॉप्टर शॉट शक्ति और तकनीक के मामले में भाला फेंकने जैसा है।

खेल के दौरान अंधविश्वासी होने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं अपने इवेंट के दिन शांत रहने की कोशिश करता हूं। मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचता। मैं सिर्फ अपना 100 प्रतिशत देने पर ध्यान केंद्रित करता हूं। मैं शांत रहने, अच्छा खाना खाने और अच्छी तरह आराम करने की कोशिश करता हूं।

भाला फेंकने वाले इस दिग्गज ने मैदान पर और मैदान के बाहर मिली सबसे अच्छी सलाह साझा करते हुए कहा, यह सलाह मेरे कोच जान जेलेजनी से मिली, जिन्होंने 98.48 मीटर की दूरी से भाला फेंकने में विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। जब भी मैं भाला फेंकता हूं, मैं बहुत ऊर्जावान रहता हूं, लेकिन वह मुझसे कहते हैं कि मुझे प्रवाह में दौड़ना चाहिए।

यह तंग महसूस नहीं होना चाहिए - मुझे बिना किसी तनाव के 18 साल के बच्चे की तरह दौड़ना चाहिए। मैं धीरे-धीरे प्रवाह की अवधारणा को समझ रहा हूं। मुझे लगता है कि किसी भी खेल में प्रवाह बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, रोजर फेडरर - वह इतनी शालीनता और लय के साथ खेलते थे कि ऐसा कभी नहीं लगा कि वह बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। मैं इसे अपने प्रशिक्षण में लाने की कोशिश कर रहा हूं। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 जेवलिन थ्रो इवेंट को 5 जुलाई को शाम 7 बजे से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (एसएस 1 हिंदी और एसएस 2) और जियोहॉटस्टार पर देखें।